

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ४] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी २३, १९७१/माघ ३, १८९२

No 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 23, 1971/MAGHA 3, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड—(ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर) केंद्रीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गए विधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 5th January 1971

S.O. 366.—In exercise of the powers conferred by section 21 and sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notifications (i) No. 434/POND/66, dated the 4th August, 1966, (ii) No. 434/POND/63(2), dated the 6th July, 1963 and (iii) No. 434/POND/66(2), dated the 4th January, 1967, the Election Commission hereby appoints, in respect of the Parliamentary Constituency in the Union Territory of Pondicherry, specified in column 1 of the Table below:—

- the officer specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table to be the Returning Officer; and
- the officers specified in the corresponding entries in column 3 of the said Table to be the Assistant Returning Officers.

TABLE

Serial No. and name of the constituency	Returning Officer	Assistant Returning Officer
1	2	3
1. Pondicherry	The Collector-cum-District Magistrate, (Independent) Pondicherry.	1. The Deputy Collector, (Revenue) Pondicherry. 2. The Deputy Collector (Excise) Pondicherry. 3. The Deputy Collector (Revenue) Karaikal. 4. The Deputy Collector (Revenue) Mahe. 5. The Deputy Collector (Revenue) Yanam.

[No. 434/POND/70.]

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1971

एस० ओ० 366.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 तथा धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपनी अधिसूचना (i) सं० 434/पांडिचेरी/66, तारीख 4 अगस्त, 1966 (ii) सं० 434/पांडिचेरी/63 (2) तारीख, 6 जुलाई, 1963 और (iii) सं० 434/पांडिचेरी/66(2), तारीख 4 जनवरी, 1967 को अधिकांश करते हुए निर्वाचन आयोग एतद्वारा निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में के संजदीय निर्वाचन क्षेत्र के बारे में :—

(क) उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर; और

(ख) उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को सहायक रिटर्निंग आफिसर, नियुक्त करता है।

सारणी

क्रम सं० तथा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	रिटर्निंग आफिसर	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2	3
1 पांडिचेरी कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (स्वतंत्र) पांडिचेरी		1—उप कलक्टर (राजस्व), पांडिचेरी। 2—उप कलक्टर (आयतारी), पांडिचेरी। 3—उप कलक्टर (राजस्व), कराईकल। 4—उप कलक्टर (राजस्व), माहे। 5—उप कलक्टर (राजस्व), यानम।

[सं० 434/पांडिचेरी/70]

ORDER

New Delhi, the 3rd January 1971

S.O. 367.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jagdish Singh, S/o. Shri Ujagar Singh, R/o. village Mohabatpur Kairauli, Tehsil Shikohabad, District Mainpuri, Uttar Pradesh a contesting candidate for Mid-term General elections, 1969 to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 343-Shikohabad Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And, whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jagdish Singh, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/343/69(168).]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जनवरी 1971

एन० ओ० 367.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये मन्त्राधि साधारण निर्वाचन 1969 के लिये 343-शिकोहाबाद सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जगदीश सिंह सुपुत्र श्री उजागर सिंह, ग्राम मोहबतपुर, केरावली, तहसील शिकोहाबाद, जिला मैथुरा, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा श्रेष्ठ निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

2. और यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

3. अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अतः उक्त श्री जगदीश सिंह को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/343/69 (168)]

आदेश से,

ए० एन० सेन, सचिव।

New Delhi, the 7th January 1971

S.O. 368.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its notification No. 434/MT/70, dated the 24th November, 1970 namely:—

In column 3 of the Table appended to the said notification,—

- (i) against Serial Nos. 3-Kolaba, 12-Malegaon, 15-Jalgaon, 32-Bhir, 40—Baramati, 41—Satara, 42—Karad, 43—Sangli and 44—Hatkanangale, for the existing entries at 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 3 and 3 respectively, the entries “Special Land Acquisition Officer, Kal Project, Roha”, “Special Land Acquisition Officer (Irrigation) No. I, Nasik”, “Sub-Divisional Officer, Chalisgaon Division, Jalgaon”, “District Supply Officer, Bhir”, “Special Land Acquisition Officer, Bhima Irrigation Project, Sholapur”, “Resident Deputy Collector, Satara”, “Special Land Acquisition Officer No. I (General), Satara”, “Special Land Acquisition Officer, General (I), Sangli” and “Sub-Divisional Officer, Shahuwadi Division, Kolhapur” shall be substituted; and
- (ii) against Serial No. 36-Ahmednagar, after entry 3, the entries “4. Special Land Acquisition Officer (Command Area) Mula Project, Ahmednagar” and “5. Special Land Acquisition Officer, Mula Project, Ahmednagar” shall be added.

[No. 434/MT/70.]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

नई दिल्ली, 7 जनवरी 1971

एस० ओ० 368.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्वारा निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना सं० 434/महा०/70 तारीख 24 नवम्बर, 1970, में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 3 में :—

(i) क्रम सं० 3-कोलाबा, 12-मालेगांव, 15-जलगांव, 32-भिर, 40-बारामती 41-सतारा 42-करद, 43-सांगली और 44-हत्कानगाले के सामने, क्रमशः विद्यमान प्रविष्टियों सं० 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 3, और 3 के स्थान पर “विशेष भूमि अधिग्रहण आफिसर, कल प्रायोजना, रोहा” “विशेष भूमि अधिग्रहण आफिसर (सिंचाई) सं 1, नासिक”, “उपखंड आफिसर, चालिसगांव प्रखंड, जलगांव” “जिला प्रभाय आफिसर, भिर”, “विशेष भूमि अधिग्रहण आफिसर, भीमा सिंचाई प्रायोजना, शोलापुर”, “आवास उप-कलक्टर, सतारा”, “विशेष भूमि अधिग्रहण आफिसर सं० 1 (सामान्य) सतारा”, “विशेष भूमि अधिग्रहण आफिसर, सामान्य (1), संगली” और “उपखंड आफिसर, शाहुवादी प्रखंड, कोल्हापुर” प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी।

(ii) क्रम सं० 35 अहमदनगर के सामने, प्रविष्टि 3 के पश्चात्, “4-विशेष भूमि अधिग्रहण आफिसर (कमान्ड एरिया) मुला प्रायोजना, अहमदनगर” और “5-विशेष भूमि अधिग्रहण आफिसर, मुला प्रायोजना, अहमदनगर” प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी।

[सं० 434/महा/70]

आदेश से,

के० एस० राजगोपालन, सचिव।

New Delhi, the 11th January 1971

S.O. 369.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that in column 3 of the Table appended to its notification No. 434/GJ/70, dated the 4th January, 1971, for the existing entry No. 5, against "1-Kutch", the entry "Deputy District Development Officer (Revenue), District Panchayat, Kutch-Bhuj" shall be substituted.

[No. 434/GJ/70.]

By Order,

ROSHAN LAL, Secy.

नई दिल्ली 11, जनवरी 1971

एस० ओ० 369.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्वारा निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना सं० 434/गुज०/70, तारीख 4 जनवरी, 1971 के साथ संलग्न सारणी के मद "1-कच्छ" के सामने, स्तम्भ 3 में विद्यमान प्रविष्टि सं० 5 के स्थान पर, "उप जिला विकास आफिसर (राजस्व), जिला पंचायत, कच्छ-भुज" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

[सं० 434/गुज०/70]

आदेश है,

रोशन लाल, सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 28th December 1970

S.O. 370.—Shri G. S. Swell vacated the office of Deputy Speaker of Lok Sabha on the 27th December, 1970 on the dissolution of the Lok Sabha on that day.

[No. 13/1/70/T.]

S. L. SHAKDHER, Secy.

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1970

एस० ओ० 370.—श्री जी० जी० स्वेल ने, 27 दिसम्बर, 1970 को लोक-सभा भंग कर दिये जाने के फलस्वरूप, उस तारीख से लोक सभा के उपाध्यक्ष का पद छोड़ दिया।

[सं० 13/1/70/टी०]

श्यामलाल शकधर, सचिव।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 14th January, 1971

S.O. 371.—In pursuance of section 3 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment to the

Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No.-S.O. 2709, dated the 3rd July, 1969, namely:—

In the said Notification, for the expression "1st March, 1971", the expression: "1st April, 1971" shall be substituted.

[No. 9/30/69-CTU.]

A. CHANDRA SEKHAR,

Registrar General, India & *ex-officio*, Jt. Secy..

गृह मंत्रालय

(भारत के महापंजीकार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 14 जनवरी 1971

का० आ० 371.—जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2709 तारीख 3 जुलाई 1969 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "1 मार्च, 1971" पद के स्थान पर "1 अप्रैल, 1971" पद प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[9/30/69-सी० टी० य०।]

ए० चन्द्र शेखर,

भारत के महापंजीकार और पदेन संयुक्त सचिव,।

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 13th January 1971

S.O. 372.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 299 of the Constitution, the President hereby directs that the contracts and assurances of property made in the exercise of the executive power of the Union, in so far as they relate to the Central Hydro-Electric Projects, may be executed on his behalf as follows:—

A. In the case of Central Hydro-Electric Projects Control Board.—All service arrangements pertaining to Gazetted Class I and II officers, by the Deputy Secretary (E) Ministry of Irrigation & Power. Agreements relating to the service conditions of other officers, by the authority competent to make the appointments concerned.

B. In the case of Central Hydro-Electric Projects, viz., Loktak Hydro-Electric Projects, Baira-Siul Hydro-Electric Project and Salal Hydro-Electric Project.—

1. Contracts and other instruments relating to advances granted to Government servants for the purchase of motor cars, motor cycles, cycles or houses or for building houses or for medical attendance and treatment or for festivals, marriages, funeral or other ceremonies or for floods etc. transfer and tour, or advances of pay to persons proceeding on deputation abroad or advances in respect of the Travel Concessions Scheme during regular leave, by the authorities granting the advances.

2. All service agreements pertaining to the service conditions of officers by the authority competent to make the appointments concerned.

3. Agreements relating to lease, hire and taking on rent or purchase of land or other immovable property like houses or other buildings, by the Chief Engineer/Deputy Chief Engineer or Superintending Engineer or Executive Engineer.

4. Contracts and other instruments in respect of accommodation provided in rented buildings (i) for hostels tiffin rooms etc. (ii) for the protection of conveyances belonging to the staff working in such rented buildings (iii) for cooperative stores/societies/banks/canteens run by Employees' Association/Societies, by the Chief Engineer/Deputy Chief Engineer in respect of accommodation hired for his offices and by the Superintending Engineer in respect of accommodation hired for his office as well as for his subordinate offices.

5. Contracts for catering in hostels and tiffin rooms or for the protection of conveyance belonging to the staff working in public buildings, by the personal Assistant to Chief Engineer/Deputy Chief Engineer or Administrative Officer so far as the Chief Engineer's/Deputy Chief Engineer's Office is concerned and by Superintending Engineer in respect of his offices and offices subordinate to him.

6. Surety bonds relating to the grant of pension or provisional pension to Government servants or to displaced Government servants, by the authority sanctioning the pension or provisional pension.

7. Contracts and other instruments relating to the payment of advance subscription for the purchase of news papers, magazines, periodicals etc., by the Chief Engineer/Deputy Chief Engineer in respect of his office and by the Superintending Engineer in respect of his office and offices subordinate to him.

8. Security bonds of Cashiers and other Government servants or their sureties to secure the due execution of an office or the due accounting for money or other property received by virtue thereof, by the Chief Engineer/Deputy Chief Engineer in respect of the Chief Engineer's/Deputy Chief Engineer's office and by the Superintending Engineer concerned in respect of offices under him.

9. (a) (i) All instruments relating to purchase, supply, conveyance or carriage of materials, stores and machinery;

(ii) All instruments relating to the execution of works of all kinds connected with building, bridges, roads, canals, tanks reservoirs, docks and harbours and embankments, generation and transmission of electricity and instruments relating to construction of water-works, sewage works, the erection of machinery, the working of coal mines and bulk supply of electricity.

(iii) bonds of auctioneers and security bonds for the due performance and completion of works;

(iv) leases for grazing cattle on canal banks or road sides, for fishing in canals, for the cultivation of lands, water power and instruments relating to sale of grass, trees or other produce on roadsides or in plantations;

(v) all instruments connected with the reconveyance of property given as security;

(vi) agreements for the recovery of fines and account of drift woods or other timber passing into a canal;

(vii) agreements relating to crossing of canals roads and bunds; and

(viii) instruments connected with the collection or framing of tolls at bridges or ferries or other means of communication; by the Chief Engineer/Deputy Chief Engineer, Superintending Engineers or Executive Engineers or Sub-Divisional Officer and Purchase Officer;

(b) agreements relating to the loan of tools and plant to contractors and others, by the Superintending Engineers or Executive Engineers;

(c) contracts, agreements and the like which can be executed by any authority can also be executed by an authority superior to it.

10. Instruments pertaining to all other items; by the Chief Engineer/Deputy Chief Engineer, even if the items fall outside the purview of the powers delegated to him, provided that the proposal relating to such items has been accepted by the competent authority.

[No. F. 11/40/70-EL-II.]

K. C. KRISHNAMURTI, Dy. Secy.

सिचाई व बिजली मंत्रालय

नई, दिल्ली, 13 जनवरी, 1971

सा०प्रा० 372.—संविधान के अनुच्छेद 299 की धारा (1) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, एतद्द्वारा, आदेश देते हैं कि केन्द्रीय सरकार की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति के संबंध में दिए गए ठेके और आश्वासन, जहाँ तक उनका सम्बन्ध केन्द्रीय पन-बिजली परियोजनाओं से है, उनकी ओर से, निम्न प्रकार से कार्यान्वित किए जाएँ :

(क) केन्द्रीय पन-बिजली परियोजना नियंत्रण बोर्ड के सम्बन्ध में।

श्रेणी I और II के राजश्वित अधिकारियों के सम्बन्ध में सभी सेवा प्रबन्ध, उपसचिव (बिजली), सिचाई व बिजली मंत्रालय द्वारा/ अन्य अधिकारियों की सेवा सम्बन्धी शर्तों से सम्बन्धित करार, सम्बन्ध नियुक्तियाँ करने के लिए सक्षम अधिकारी।

(ख) लोकल पन-बिजली परियोजना, बैरा-सिमुल पन-बिजली परियोजना और सलाल पन-बिजली परियोजना नामक केन्द्रीय पन-बिजली परियोजनाओं के सम्बन्ध में।

1. मोटर कार, मोटर साइकिल, साइकिल अथवा घरों की खरीद के लिए अथवा गृह निर्माण के लिए अथवा डाक्टरी इलाज के लिए अथवा त्योहारों, विवाह शादियों, अन्त्येष्टि, के लिए अथवा अन्य धार्मिक क्रियाओं के लिए अथवा बाढ़ों आदि, स्थानान्तरण, पर्यटन के लिए, अथवा डेपुटेशन पर विदेशों में जाने वाले व्यक्तियों के अग्रिम वेतन के लिए अथवा नियमित अवकाश के दौरान यात्रा खर्चायत स्कीम के सम्बन्ध में अग्रिम राशियों के लिए सरकारी कर्मचारियों की दी गई अग्रिम राशियों से संबंधित ठेके और अन्य दस्तावेज, अग्रिम राशियाँ स्वीकार करने वाले अधिकारियों द्वारा।

2. अधिकारियों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित सभी सेवा करार, संबंधित नियुक्तियाँ करने के लिए सक्षम अधिकारी।

3. जमीन अथवा घरों अथवा अन्य भवनों जैसी अन्य अचल सम्पत्ति पट्टे पर लेने, किराए पर लेने अथवा खरीदने से सम्बन्धित करार, मुख्य इंजीनियर/उप मुख्य इंजीनियर अथवा अधीक्षक इंजीनियर अथवा कार्यकारी इंजीनियर द्वारा।

4. (i) होस्टलों, टिफिन कक्षों आदि के लिए (ii) किराए पर लिए गए भवनों में कार्य कर रहे स्टाफ की गाड़ियों की सुरक्षा के लिए, (iii) कोआपरेटिव स्टोरो/सोसाइटियों/ बैंकों/कर्मचारियों की संस्थाओं/सोसाइटियों द्वारा चलाई गई केन्टीनों के वास्ते किराए पर लिए गए भवनों में प्रबन्धित जगह के संबंध में ठेके तथा अन्य दस्तावेज, मुख्य इंजीनियर/उप मुख्य इंजीनियर द्वारा उसके कार्यालय के लिए किराए पर ली गई जगह के संबंध में और अधीक्षक अभियंता द्वारा उसके कार्यालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों के लिए किराए पर ली गई जगह के संबंध में।

5. होस्टलों और टिफिन कक्षों में जलपान के प्रबंध के लिए तथा सार्वजनिक भवनों में कार्य कर रहे स्टाफ की गाड़ियों की सुरक्षा के लिए ठेके, मुख्य इंजीनियर/उप मुख्य इंजीनियर के व्यक्तिगत सहायक अथवा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, जहाँ तक मुख्य इंजीनियर/उप मुख्य इंजीनियर के कार्यालय का संबंध है और अधीक्षक इंजीनियर द्वारा, जहाँ तक उसके कार्यालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों का संबंध है।

6. सरकारी कर्मचारियों अथवा विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को पेन्शन अथवा अस्थायी पेन्शन देने के सम्बन्ध में जमानती बांड, पेन्शन अथवा अस्थायी पेन्शन स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा ।

7. अखबारों, मैगजीनों, पत्रिकाओं आदि को खरीदने के लिए अग्रिम अंशदान की अदायगी से सम्बन्धित ठेके तथा अन्य दस्तावेज, मुख्य इन्जिनियर/उप मुख्य इन्जिनियर द्वारा, जहां तक उस के कार्यालय का सम्बन्ध है और अग्रजत इन्जिनियर द्वारा जहां तक उसके कार्यालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों का सम्बन्ध है ।

8. खजानचियों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों अथवा उनके जामिनों के, उनके द्वारा, कार्य निष्पादन कराने के लिए अथवा धन अथवा इस कारण अन्य सम्पत्ति का उचित लेखा जोखा रखवाने के लिए, जमानती बांड, मुख्य इन्जिनियर/उप मुख्य इन्जिनियर द्वारा, जहां तक मुख्य इन्जिनियर/उप मुख्य इन्जिनियर के कार्यालय का सम्बन्ध है और सम्बद्ध अधीक्षक इन्जिनियर द्वारा, जहां तक उसके अधीन कार्यालयों का सम्बन्ध है ।

9. (क) (एक) सामग्री, स्टोर तथा गोनरी को खरीदने वाली सप्लाई, उते ले जाने से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों ;

(दो) भवनों, पुलों, सड़कों, नहरों, तालों, जलशयों, जहाजी माल घाटों और बन्दरगाहों तथा तटबन्धों, विद्युत उत्पादन और पारेषण से सम्बन्धित सभी दस्तावेज और जल-कार्यों सीवेज कार्यों के निर्माण, मशीनरी के प्रतिष्ठापन, कोयले की खानों की कार्य प्रणाली तथा बिजली की थोक सप्लाई से सम्बन्धित दस्तावेज ।

(तीन) नोनाम करने वालों के बांड तथा उचित कार्य निष्पादन और कार्यों को पूर्ण करने के लिए जमानती बांड ।

(चार) नहरों के किनारों अथवा सड़कों के दोनों तरफ पशु चराने के लिए, नहरों में मछलियां पकड़ने के लिए, जमान को खेती के लिए, पनबिजली के लिए पट्टे तथा सड़कों के दोनों तरफ अथवा बागानों में घास, पेड़ अथवा ऐसे हो कोई और उगो वस्तुओं से सम्बद्ध दस्तावेज ;

(पांच) जमानत के रूप में दी गई सम्पत्ति को दोबारा ले जाने के सम्बन्ध में सभी दस्तावेज ।

(छः) नहर में बह रही लकड़ी अथवा अन्य इमारती लकड़ी पर लगाए जुर्माने वसूल करने के लिए करार ;

(सात) नहरों, सड़कों और बन्धों को पार करार से सम्बन्धित करार ; और

(आठ) पुलों अथवा, नौकाओं अथवा अन्य संचार साधनों पर औजारों का एकत्रण अथवा फार्मिंग ;

मुख्य इन्जिनियर / उप मुख्य इन्जिनियर, अग्रजत इन्जिनियरों अथवा कार्यकारी इन्जिनियरों अथवा सब डिवाइजल अधिकारी और क्रय अधिकारी द्वारा ;

(ख) ठेकेदारों और अन्य लोगों को औजार तथा संपन्न किराये पर देने से संबंधित करार, अधीक्षक इन्जिनियर अथवा कार्यकारी इन्जिनियरों द्वारा ।

(ग) ठेके, करार तथा ऐसे ही अन्य दस्तावेज जो कि किसी भी अधिकारी द्वारा निष्पादित किए जा सकते हैं, वे उनसे बड़े किसी भी अधिकारी द्वारा निष्पादित किए जा सकते हैं ।

10. अन्य हथी मदों से सम्बन्धित दस्तावेज, मुख्य इन्जीनियर/उपमुख्य इन्जीनियर द्वारा, चाहे ये मदें उसे दी गई शक्तियों के बाहर ही क्यों न हों, लेकिन इन मामलों में शर्त यह होगी कि ऐसी मदों से सम्बन्धित प्रस्ताव सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया हो।

[सं० एफ० 11/40/70-ई० एल० 11]

के० सो० कृष्णमूर्ति, उप-सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT AND CIVIL AVIATION
(Office of the Director General of Civil Aviation)

New Delhi, the 28th October, 1970

S.O. 373.—In pursuance of sub-rule (3) of rule 78-A of the Aircraft Rules, 1937 and in supersession of Notification No. GSR 1299, dated 9th August, 1967 published in the Government of India Gazette, Part II, Section 3(i) dated 2nd May, 1967, the Director General of Civil Aviation is pleased to authorize the following officers to demand for examination Admission Tickets for entry into International and Domestic passengers booking halls and lounges and the enclosures appertaining thereto in the Delhi Airport (Palam):—

- (1) Controller of Aerodromes, Delhi Region;
- (2) Senior Aerodrome Officers, Aerodrome Officers and Assistant Aerodrome Officers posted at Delhi Airport (Palam);
- (3) Administrative Officers and Accounts Officers of the Civil Aviation Department posted at Delhi Airport (Palam);
- (4) Aerodrome Operators, Airport Ticket Clerks, Care-takers and Chowkidars posted at Delhi Airport (Palam);
- (5) Any Police Officer.

[No. 15/32/66-Rev.]

G. C. ARYA,

Director General of Civil Aviation.

**परिवहन तथा मगर विमानन में सय
सिविल विमानन क महानिदेशक का कार्यक्रम**

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1970

एस० ओ० 373.—वायुयान नियम, 1937 के नियम 78-क के उपनियम (3) के अनुसरणमें और भारत सरकार के राजपत्र, भाग II खण्ड 3(1) तारीख 2 मई 1967 में प्रकाशित अधिसूचना सं० सा० क० नि० 1299 तारीख 9 अगस्त 1967 को अधिकृत करते हुए, सिविल विमानन महानिदेशक एतद्द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट (पालम) पर अन्तर्राष्ट्रीय और देशीय यात्री बुकिंग हॉलों और लॉजों तथा उन से संलग्न घरों में प्रवेश के लिए प्रवेश टिकटों की जांच के लिए मांग करने को प्राधिकृत करता है :—

- (1) हवाई अड्डा नियन्त्रक दिल्ली क्षेत्र;
- (2) दिल्ली एयरपोर्ट (पालम) पर तैनात ज्येष्ठ हवाई अड्डा अधिकारी, हवाई अड्डा अधिकारी और सहायक हवाई अड्डा अधिकारी;
- (3) सिविल विमानन विभाग के दिल्ली एयरपोर्ट (पालम) पर तैनात प्रशासनिक अधिकारी और लेखा अधिकारी;
- (4) दिल्ली एयरपोर्ट (पालम) पर तैनात हवाई अड्डा आपरेटर, एयरपोर्ट टिकट लिपिक, रखवाल और चौकीदार;
- (5) कोई पुलिस अधिकारी।

[सं० 15/32/60 राजस्व]

जी० सी० आर्य

सिविल विमानन महानिदेशक

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

COST AND WORKS ACCOUNTANTS

New Delhi, the 18th December, 1970

S.O. 374.—In pursuance of clause (b) of regulation 20 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry (Department of Company Law Administration) No. S.R.O. 2118, dated the 19th September, 1959, namely:—

In the said notification, after item 30 the following item shall be inserted, namely:—

“31. A pass in the Antrim Examination of Kashi Vidyapith, Varanasi”.

[No. 10/55/69-IGC]

M. C. VARMA, Under Secy.

कम्पनी कार्य विभाग

लागत और सैकर्म लेखापाल

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर 1970

का० आ० 374.— लागत और सैकर्म लेखापाल विनियम, 1959 के विनियम 20 के खण्ड (ख) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 2118 तारीख 19 सितम्बर, 1959 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, मध 30 के पश्चात् निम्नलिखित मध अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—31 काशी विद्यापीठ वाराणसी की अन्तरिम परीक्षा में उत्तीर्ण”

[सं० 10/55/69-आई० जी० सी०]

एम० सी० वर्मा, अवर सचिव।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 7th January 1971

S.O. 375.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and of all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Expenditure) No. F. 7(5)-EV/69, dated the 15th September, 1969, relating to the amendment of Rule 56 of the Fundamental Rules, namely:—

In the said notification, in rule 1, sub-rule (2) shall be omitted and in sub-rule (i), the brackets and figure “(1)” shall be omitted.

[No. F. 7(5)-EV/69.]

MEHAR SINGH, Under Secy.

(Department of Banking)

New Delhi, the 8th January 1971

S. O. 376.—Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, as on the 1st January, 1971.

BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	29,67,45,000
		Rupee Coin	2,76,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	4,30,000
		Bills Purchased and Discounted:—	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	172,00,00,000	(a) Internal	20,36,000
		(b) External
		(c) Government Treasury Bills	19,28,35,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	37,00,00,000	Balances Held Abroad*	93,89,85,000
		Investments**	99,69,44,000
		Loans and Advances to:—	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	95,00,00,000	(i) Central Government
		(ii) State Governments @	16,39,74,000
		Loans and Advances to:—	
Deposits:—		(i) Scheduled Commercial Banks †	350,96,95,000
(a) Government—		(ii) State Co-operative Banks ††	298,91,46,000
(i) Central Government	263,72,76,000	(iii) Others	2,50,65,000
(ii) State Governments	10,17,02,000		

		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund —	
(b) Banks—		(a) Loans and Advances to:—	
(i) Scheduled Commercial Banks	200,98,15,000	(i) State Governments	34,20,79,000
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	7,91,06,000	(ii) State Co-operative Banks	22,28,99,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	79,76,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	..
(iv) Other Banks	27,05,000	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	9,57,02,000
(c) Others		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund —	
Bills Payable	63,81,01,000	Loans and Advances to State Co-operative Banks	5,29,94,000
Other Liabilities	99,34,08,000	Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund —	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	27,93,71,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
		Other Assets	39,64,09,000
	Rupees 1201,55,85,000		Rupees 1201,55,85,000

* Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

** Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

† Includes Rs. 145,45,50,000/- advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

†† Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

On the 6th day of January, 1971.

An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 1st day of January 1971

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Ra.	Ra.	ASSETS	Ra.	Ra.
Notes held in the Banking Department	29,67,45,000		Gold Coin and Bullion:—		
			(a) Held in India	182,53,11,000	
Notes in circulation	4009,29,16,000		(b) Held outside India	
Total Notes issued		4038,96,61,000	Foreign Securities	311,42,00,000	
			TOTAL		493,95,11,000
			Rupee Coin		57,91,29,000
			Government of India Rupee Securities		3487,10,21,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper
TOTAL LIABILITIES		4038,96,61,000	TOTAL ASSETS		4038,96,61,000

Dated the 6th day of January, 1971

S. JAGANNATHAN,
Governor.

[No. F.3(3)-BC/71.]

K. YESURATNAM, Under Secy.

वित्त मंत्रालय
(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1971

एस० नो० 376.—1 जनवरी, 1971 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुक्ता पूंजी	5,00,00,000	नोट	29,67,45,000
भारक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	2,76,000
		छोटा सिक्का	4,30,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	172,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल :—	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	37,00,00,000	(क) देशी	20,36,000
		(ख) विदेशी
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घ कालीन क्रियाएं) निधि	95,00,00,000	(ग) सरकारी खजाना बिल	19,28,35,000
जमा राशियां :—		विदेशों में रखा हुआ बकाया*	93,89,85,000
(क) सरकारी		निवेश**	99,69,44,000
(i) केन्द्रीय सरकार	263,72,76,000	ऋण और अग्रिम :—	
(ii) राज्य सरकारें	10,17,02,000	(i) केन्द्रीय सरकार को
		(ii) राज्य सरकारों को @	167,39,74,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम :—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	200,98,15,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को †	350,96,95,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7,91,06,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को ††	298,91,46,000
		(iii) दूसरों को	2,50,65,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	

देयताएं	रुपये	प्रास्तियां	रुपये
(क) ऋण और अग्रिम :—			
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	79,76,000	(i) राज्य सरकारों को	34,20,79,000
(iv) अन्य बैंक	27,05,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	22,28,99,000
(ग) अन्य	95,54,96,000	(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को
देव बिल	63,81,01,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम :—	9,57,02,000
अन्य देयताएं	99,34,08,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	5,29,94,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश :—	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	27,93,71,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश
		अन्य प्रास्तियां	39,64,09,000
	रुपये 1201,55,85,000		रुपये 1201,55,85,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

†रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 (4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मियादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 145,45,50,000 रु. शामिल हैं।

††राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

तारीख : 6 जनवरी 1971

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में जनवरी, 1971 को 1 तारीख को समाप्त हुए अकाउंट्स के लिये लेखा

इस विभाग

रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपय	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए		सोने का सिक्का और बुलियन :—		
नोट 29,67,45,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,53,11,000	
संचालन में नोट 4009,29,16,000		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ		
जारी किए गए कुल नोट	4038,96,61,000	विदेशी प्रतिभूतियां	311,42,00,000	
		जोड़े		493,95,11,000
		रुपये का सिक्का		57,91,29,000
		भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां		3487,10,21,000
		देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र
कुल देयताएं ¹	4038,96,61,000	कुल आस्तियां		4038,96,61,000

एम० जगन्नाथन,

मबनर ।

तारीख: 6 जनवरी, 1971

[नं० एफ० 3(3)-बी० सी०/71]

के० प्रेमचंद, अनु सचिव ।

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 12th January 1971

S.O. 377.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 3), Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Maldanpat and Birhnipat Bauxite Mines of Messrs Hindustan Aluminium Corporation Limited, Post Office Richughuta, District Palamau (Bihar), and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th January, 1971.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 3) AT DHANBAD

REFERENCE No. 22 OF 1970

PRESENT:

Shri Sahcedanand Sinha, M.A.M.L., Presiding Officer.

PARTIES:

Employers in relation to the Management of Maldanpat and Birhnipat Bauxite Mines,

Vs.

Their workmen.

APPEARANCES:

For employers.—Sri Shyamnandan Sahay, Law Officer.

For workmen.—Sri Mahabir Ram Verma, Joint Secretary, Ranchi District Bauxite and China Clay Mines Employees Union.

INDUSTRY: Bauxite Mine.

STATE: Bihar.

Dhanbad, dated the 28th of December, 1970

AWARD

1. The Central Government being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Maldanpat and Birhnipat Bauxite Mines of Messrs Hindustan Aluminium Corporation Limited, Post Office Richughuta, District Palamau (Bihar) and their workmen, by its order No. 10/16/70-LRIV, dated the 24th of April, 1970 referred under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 to this Tribunal for adjudication the dispute in respect of the matters specified in the Schedule annexed thereto. The Schedule is extracted below:—

SCHEDULE

‘Whether the demand of the workmen of Maldanpat and Birhnipat Bauxite Mines of Messrs Hindustan Aluminium Corporation Limited, Post Office Richughuta, District Palamau (Bihar) for 20 per cent Profit Sharing Bonus for the year ending 31st December, 1968 is justified? if not, to what relief are they entitled?’

2. Shri Mahabir Ram Verma, Joint Secretary filed written statement on 17th July 1970 for and on behalf of the workmen. The employers did not file their written statement. However, this is of little consequence since the matter has been settled amicably between the parties.

3. The parties filed a joint petition stating that an overall settlement regarding various matters including the matter under reference has been arrived at between the parties in terms of which in addition to the Bonus already paid for the year 1969 the management has made an ex-gratia payment of 10 days wages to all the workmen working at Maldanpat and Birhnipat Bauxite Mines of M/s. Hindustan Aluminium Corporation Limited and no dispute further exists between the parties and prayed that a no dispute award may be made.

4. The joint petition is verified by Sri Shyam Nandan Sahay, Law Officer for and on behalf of Hindustan Aluminium Corporation Limited and by Sri Mahabir Ram Verma, Joint Secretary of the Union for and on behalf of the workmen.

5. In view of the above I hold that no more dispute exists between the parties and accordingly I pass a 'NO DISPUTE' award in the matter. This may be submitted to the Central Government under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Sd.) SACHIDANAND SINHA,
Presiding Officer.
[No. 10/16/70-LR-IV.]

New Delhi, the 13th January 1971

S.O. 378.—In pursuance of section 17 of the Industrial disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. 2) Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs M. S. Sawhney and Sons, Chandivali, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th January, 1971.

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO 2.
BOMBAY**

REFERENCE No. CGIT-2/15 OF 1969

**Employers in Relation to the Management of Messrs M. S. Sawhney and Sons,
Chandivali, Bombay**

**AND
Their Workmen**

PRESENT:

Shri N. K. Vani, Presiding Officer.

APPEARANCES:

For the employer—Sri N. B. Shetye, Advocate.

For the workmen—Shri G. R. Khanolkar, Vice-President, Maharashtra Khan Kamgar Union, Bombay.

STATE: Maharashtra

INDUSTRY: Stone Quarry.

Bombay, dated the 26th December, 1970

AWARD

By Order No. 36(21)/69-LRIV, dated 2nd September, 1969, the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) in exercise of the powers conferred by clause (d) of Sub-Section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Messrs M. S. Sawhney and Sons, Chandivali, Bombay and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule mentioned below:—

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Messrs M. S. Sawhney and Sons, Chandivali, Bombay, in terminating the services of Sarvashri Sangram Dharma Kamble and Sadashiv Eknath, with effect from the 25th January, 1969 and the 4th May, 1968 respectively was justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled.”

2. Facts giving rise to this reference are as follows:—

- (i) Sarvashri Sangram Dharma Kamble and Sadashiv Eknath were in the service of Messrs M. S. Sawhney and Sons, Chandivali, Bombay (hereinafter referred to as 'the Company'). Their services were terminated without serving notices on them. They were not served with any show cause notice. They were not given any reason for refusing work. No charge-sheet was served on them. No enquiry was held against them. They, therefore, demanded that they should be reinstated in service with full back wages and continuity of service.
- (ii) It appears that the Union took up their cause to the Assistant Labour Commissioner (C), Bombay. He tried to bring about conciliation but in vain. He, therefore, submitted his failure of conciliation report to the Government.

- (iii) On the receipt of this report, the Central Government referred this dispute to this Tribunal for adjudication.

3. After the receipt of the reference, notices were issued to the parties to file their written settlements. In pursuance of this notice, the Manager of the company has filed written statement at Ex. 1/E. According to the company:—

- (i) Shri Sangram Dharma Kamble was working with the company as an unskilled labourer on crusher. He is not a workman within the meaning of Section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947. Therefore this Court has no jurisdiction to entertain his dispute.
- (ii) During the conciliation proceedings the company made offer to allow Shri Kamble to resume his duties as an unskilled labour before 15th May 1969, but the Union representative was not ready to accept the offer of the management and demanded that the workman should be reinstated as a Machine Stone Filer.
- (iii) This employee was not dismissed, but he had left the service on his own accord. There is neither victimisation, nor unfair labour practice on the part of the company. The question of reinstatement therefore, does not arise.
- (iv) As regards Shri Sadashiv Eknath, he was working in the company as a temporary hand and his service is as follows:—
 From 26th June, 1967 to 30th June, 1967
 From 1st July, 1967 to 22nd August, 1967
 From 25th October, 1967 to 26th October, 1967
 From 25th January, 1968 to 3rd April, 1968 and
 on 3rd May, 1968.
- (v) He did not report for duty as and from 4th May, 1968. As he is not in the employment as and from 4th May, 1968, the question of reinstatement in service does not arise.

- (vi) The demand of reinstatement demanded by the employees be rejected.

4. Shri Krishna Joshi, General Secretary, Maharashtra Kamgar Union, Bombay for and on behalf of the workmen employed by Messrs M. S. Sawhney and Sons, Chandivali Bombay, has filed written statement at Ex. 2/W. According to him:—

- (i) Shri S. D. Kamble was one of the persons responsible for the formation of the trade union. He represented the grievances of the workmen to the management in respect of service conditions including sanitary conditions etc. This was not liked by the management. On account of this they illegally terminated his service without passing any written order. The action of the company in terminating his services is improper and illegal as the termination of the service has taken place without compliance with any requirements of the principles of natural justice. It is, therefore, prayed that this workman be reinstated with continuity of service and back wages.
- (ii) As regards Shri Sadashiv Eknath, he was stopped from work without assigning any reasons from 5th April, 1969. He was employed by the company in the year 1965. During the course of employment, he met with an accident and sustained injuries. On 19th February, 1969 he was sent to Lokmanya Tilak Municipal General Hospital, Slon and treated there from 19th February, 1969 to 4th April, 1969. At the time of discharge from the hospital, he was given necessary certificate as required under the relevant provisions of the workmen's Compensation Act by the Medical Officer-in-charge. Thereafter, he went to the company on 5th April, 1969. The Company refused to give him any work. It removed him from the service as he met with an accident. It is not true that the workman left his job on his own accord. The action of the company therefore is an organised act of victimisation. It lacks in the *bona fides*, or in any accepted principles of decency or principles of natural justice. The workman be reinstated with continuity of service and back wages.

5. The case was adjourned from time to time at the request of the parties. On 23rd December 1970, (Shri G. R. Khanolkar, Advocate for the Union and Shri Krishna Joshi, General Secretary of the Union have given applications as mentioned below:—

“That the two workmen Shri Sangram Dharma and Shri Sadshiv Eknath were sent messages and letters by the Union to remain present in this

Hon'ble Court in connection with the above reference. As the Union could get no response from the two workers, it is difficult for the Union to conduct the above matter in the absence of the two workmen concerned.

In view of this it is prayed that this Hon'ble Tribunal be pleased to allow the Union to withdraw the reference.

The Hon'ble Tribunal may therefore pass appropriate directions in terms of the said prayer."

6. In the present case the two employees have not remained present and come in the witness box to say that they had not left the service of the company of their own accord.

7. On the admission of the company in its written statement, it has not terminated the services of the two employees and they had left the service on their own accord.

8. It appears from the written statement Ex. 1/E that the company had offered employment to Shri Kamble but the Union on his behalf refused to accept, the same and insisted that he should be reinstated to the original post of Machine Stone Filler. The company expressed its inability to do so on the ground that it has engaged another employee in that post on account of the absence of this employee and that work of that employee was also found satisfactory.

9. As regards the other employee Shri Sadashiv Eknath, the company submitted that he was a temporary worker and that he had left the work of his own accord on 4th May, 1968. He was not dismissed from service.

10. As the company's stand is that both the employees left the job of the company of their own accord, it was necessary for the workmen to come in the witness box to say that they have not left the job on their own accord.

11. The Union by its application referred to above prays that it should be allowed to withdraw the reference. There is no provision in the Industrial Disputes Act, under which the Tribunal can allow the Union to withdraw the reference.

12. As the two employees are not remaining present to contest the reference, it can be inferred that they are no longer interested in continuing this reference. In pressing their demands and getting redress from the Tribunal. It may be that they might have got some employment somewhere else and that they are not anxious to get reinstatement with continuity of service and back wages in the company. I, therefore, hold that the dispute raised by the employees no longer survives. In the end I pass the following order:—

ORDER

(i) It is hereby declared that the dispute referred to this Tribunal no longer survives and that no dispute award is passed.

(ii) No order as to costs,

(Sd.) N. K. VANI,

Presiding Officer,
Central Government Industrial Tribunal No. 2,
Bombay.

[No. 36(21)/69-LR-IV.]

S.O. 379.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Rajasthan, Jaipur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Borabas Stone Quarry, Shreepura, Kota owned by Madar Bux of Kota, and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th January, 1971.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, RAJASTHAN, JAIPUR

PRESENT:

Shri Gopal Narain Sharma, Presiding Officer.

CASE NO. CIT-9 OF 1970

Ref:—Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, Department of Labour and Employment, New Delhi Order No. 12(19)79-LR-IV, dated 7th September, 1970.

In the Matter of an Industrial Dispute

BETWEEN

The Patthar Khan Mazdoor Sangh, Kota

AND

Madar Bux Quarry Owners, Kota

Date of Award:

27th Noember, 1970.

AWARD

The Central Government by its order dated the 7th September, 1970 referred the following dispute between the employers in relation to the Management of Borabas Stone Quarry, Shreepura Kota and their workmen to this Tribunal for adjudication:—

“Whether the employees employed at Borabus Stone Quarry of Shri Madar bux Quarry Owner, Kota are entitled for the following paid National Festival holidays, namely:—

1. 26th January—Republic Day.
2. 15th August—Independence Day.
3. 2nd October—Gandhiji's Birthday.
4. Holy.
5. 1st May—Labour Day.
6. Rakshabandhan.
7. Dassera.
8. Diwali.
9. Id.”

When the case came up for hearing today the representatives of the parties stated that they have mutually settled the dispute out of Court and filed a memorandum of settlement so arrived at. They prayed for passing an award in terms of the settlement.

The settlement appears to be reasonable and fair. Hence an award is passed in terms of the settlement a copy of which shall form part of this award. It may be submitted to the Government for publication.

(Sd.) GOPAL NARAIN SHARMA,

Presiding Officer.

Central Govt. Industrial Tribunal(Rajasthan, Jaipur

Form “H”

(See Rule 58)

Form for memorandum of Settlement

Memorandum of Settlement In the Industrial Dispute—between the management of Shri Madar Bux Quarry owner of Borabas office Shripura Kota and their workmen represented by the Pather Khan Mazdoor Sangh, Kota over the demand of the Union regarding the granting of the paid National & Religious Festivals to the workers.

Representing the Employer.

(1) SRI MADAR ZUX

Name of the Parties

Representing the workmen

(1) SHRI MAHAVIR PD. SHARMA

(2) PATHAR KHAN MAZDOOR SANGH, KALA

Short Receipt of the Case

The management and the Union were under negotiations for some time regarding the demand of the Union for granting the national and Religious Holidays to the workers. The parties as a result of discussions and negotiations arrived at the following settlement.

Terms of Settlement

1. It is agreed that the management will grant the following national and Religious festivals to all its staff members and workers with effect from 1st January, 1970.—

1. Republic Day	1 day
2. Holi (Bhulandi)	1 day
3. Mazdoor Diwas (1st May)	1 day
4. Independence day (15th Aug.)	1 day
5. Raksha Bandhan	1 day
6. Dashera	1 day
7. Deepavali	1 day
8. Gandhi Diwas	1 day
9. Id.	1 day

and any other day declared by Govt. as holiday.

2. The arrear of the paid holidays shall be paid on the date of 30th Dec., 1970.

3. In view of the above settlement the Union agreed to move the joint petition for award in terms of settlement in Case No. CIT/9/70 pending before Industrial Tribunal Rajasthan, Jaipur before which the reference (Made by the under secretary Deptt. of Labour & Employment, Ministry of Labour Employment & Rehabilitation, Govt. of India, New Delhi vide his order... dated 9th September 1970) is pending for adjudication in the matter of demand for paid holidays.

4. In view of the above settlement the Union withdraws its demands raised vide its letter 31/77 dated 23rd March, 1970.

(Sd.) MADAR BUX,
Employer
Witnesses:

1.
2.

1. (Sd.) M. P. SHARMA,
President.

[No. 12(19)/70-LRIV.]

P. C. MISRA, Dy. Secy.

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 13th January 1971

S.O. 380.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2517, dated the 21st June, 1969 the Central Government having regard to the location of the Eluru Water Works Pumping Supply Station, Eluru West Godavari District, Andhra Pradesh, in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said works from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the 1st March, 1970 upto and inclusive of the 28th February, 1971.

[No. F.8(18)/68-HL.]

श्रम, रोजगार और पुनर्वसि मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1971

का० आ०—380 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 73 च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम रोजगार और पुन

वॉस मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2517 तारीख 21 जून, 1969 के क्रम ; केन्द्रीय सरकार एलुरु मेंवाटर-वर्स पम्पिंग सप्लाई स्टेशन, एलुरु, वैस्ट गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश की ऐसी क्षेत्र में, जिस; में उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उतबन्ध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त वर्क्स को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से प्रथम मार्च, 1970 से 28 फरवरी 1971 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की कालाविधि के लिए एतद्वारा छूट देती है।

[सं० फा० 6(18)/68-एच० आई०]

S.O. 381.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government having regard to the location of the Industrial Extension Centre, Kolhapur in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force thereby exempts the said factory from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a period of one year with effect from the 13th October, 1970 upto and inclusive of the 12th October, 1971.

[No. F.602(45)/70-HI.]

का० आ० 381—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73 बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विस्तार केन्द्र कोल्हापुर की ऐसी क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उतबन्ध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से 13 अक्टूबर, 1970 से 12 अक्टूबर, 1971 तक जिस; में वह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की कालाविधि के लिए एतद्वारा छूट देती है।

[सं० फा० 602 (45)/70-एच० आई०]

S.O. 382.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government having regard to the location of the Geophysical and Research and Training Institute workshop, Dehradun, in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the Act are in force, hereby exempts the said workshop from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a period of one year with effect from the 30th January, 1970 upto and inclusive of the 29th January, 1971.

[No. F.602(32)/70-HI.]

का० आ० 382—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा 73 बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भूमौतिक्य और अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कर्मशाला, देहरादून की ऐसी क्षेत्र में जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उतबन्ध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कर्म शाला को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय से संदाय से 30 जनवरी, 1970 से 29 जनवरी, 1971 तक जिस; वह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की कालाविधि के लिए एतद्वारा छूट देती है।

[सं० फा० 602 (32)/70-एच० आई०]

S.O. 383.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3275, dated the 5th August, 1969, the Central Government having regard to the location of the Laundry Plant at the Medical College and Hospital, Nagpur, in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said laundry from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter

VA of the said Act for a further period of one year with effect from the 5th August, 1970, upto and inclusive of the 4th August, 1971.

[No. F-601(23)/70-HI.]

का० आ० 383.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 73 च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3275 तारीख 5 अगस्त, 1969 के क्रम में केन्द्रीय सरकार शिक्षित महांविद्यालय एवं चिकित्सालय, नागपुर के लाण्डी प्लान्ट की ऐसी क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त लाण्डी को उक्त अधिनियम के अध्याय 5—क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संन्दाय से 5 अगस्त, 1970 से 4 अगस्त 1971 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा छूट देती है।

[सं० फा० 601 (23) /70-एच० आई०]

S.O. 384.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 987, dated the 3rd March, 1970 the Central Government having regard to the location of the factory, namely, Aluminium Industries Limited, Hyderabad in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said factory from the payment of the employers' special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of six months with effect from the 1st August, 1970 upto and inclusive of the 31st January, 1971.

[No. F.601(27)/70-HI.]

का० आ० 384.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार) की अधिसूचना सं० का० आ० 987 तारीख 3 मार्च 1970 के क्रम में केन्द्रीय सरकार एलमिनियम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, हैदराबाद नामक कारखाने की ऐसी क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5—क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संन्दाय से 1 अगस्त, 1970 से 31 जनवरी, 1971 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, 6 मास की और कालावधि के लिए एतद्वारा छूट देती है।

[सं० फा० 601(27) /70-एच० आई०]

New Delhi, the 15th January 1971

S.O. 385.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Goa Urban Co-operative Bank Limited, Menezes, Braganza Road, Panjim, Goa including its branches at Margao (near Cine Lata) and Aisha Theatre Building, Ponda have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1969.

[No. 8/128/70/PF-II.]

नई दिल्ली, 15 जनवरी 1971

का० आ० 385.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स गोवा ग्ररबन काआपेरेटिव बैंक लिमिटेड, मेनेजेस ब्रगन्जा रोड, पंजिम, गोवा नामक बैंक स्थापन जिसमें इसकी

मारगोवा (साइन लता के निकट) और ऐशा थियेटर बिल्डिंग, पोंडा की शाखाएं सम्मिलित हैं से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद् द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1969 की जून के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० 8/128/70-पी० एफ० 2]

S.O. 386.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and all the employees in relation to the establishment known as The Iron Steel and Hardware Merchants and Manufacturers' Chamber of India, 410, 4th Floor, Loha Bhavan, P.D. Mello Road, Bombay-9, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1970.

[No. 8/125/70/PF-II.]

का० आ० 386.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि दि आयरन, स्टील एण्ड हाडवेयर मर्चेन्ट्स एण्ड मैनुफैक्चरर्स चैम्बर आफ इंडिया, 410, चौथी मंजिल, लोहा भवन, पी० डी० मेलो रोड, मुम्बई-9 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और सभी कर्मचारी इस बात पर सहमत हो गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद् द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1970 के मार्च के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी

[सं० 8/125/70-पी० एफ० 2]

S.O. 387.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Messrs Lakshmi Textile Exporters Private Limited, 348, Avanashi Road, Pappanaickpalayam, Coimbatore-18 (South India) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1970.

[No. 8/95/70-PF-II(i).]

का० आ० 387.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मॅसर्स लक्ष्मी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, 348, अवनाशी रोड, पम्पनेक्केनलयम, कोयम्बटूर-18 (दक्षिण भारत) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1970 की जनवरी, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या 8/95/70-पी०एफ० 2(i)]

S.O. 388.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st January, 1970 the establishment known as Messrs Lakshmi Textile Exporters Private Limited, 348, Avanashi Road, Pappanaichennpalayam, Coimbatore-18 (South India) for the purpose of the said proviso.

[No. 8/95/70-PF(II)(ii).]

का० आ० 388.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्वारा मेसर्स लक्ष्मी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, 348, अवनशी रोड, पम्पनेक्केनपलयम, कोयम्बटूर 18 (दक्षिण भारत) नामक स्थापन को प्रथम जनवरी, 1970 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० 8/95/70-पी० एफ० 2(ii).]

S.O. 389.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Apsara Cinema, Yeotmal (Maharashtra) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall deemed to have come into force on the first day of October, 1969.

[No. 8/156/69/PF.II.]

का० आ० 389.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स अप्सरा सिनेमा, योतमल (महाराष्ट्र) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1969 के अक्तूबर, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० 8/156/69-पी०एफ०-(2)]

S.O. 390.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Buchireddipalem Co-operative Rural Bank Limited, No. K.69, Buchireddipalem Nellore, District Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall deemed to have come into force on the first day of January, 1970.

[No. 8/145/70/PF-II(1).]

का० आ० १९०—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि बिचिरेडडीपलेम कोऑपरेटिव रूरल बैंक लिमिटेड, सं० के० ६९, बुचिरेडडीपलेम, नैल्लोर जिला, आन्ध्रप्रदेश नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ (१९५२ का १९) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा १ की उपधारा (४) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना १९७० की जनवरी, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई, समझी जाएगी।

[सं० ८/१४५/७०-पी०एफ० २(१)]

S.O. 391.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st January, 1970, the establishment, known as The Buchireddipalem Co-operative Rural Bank Limited, No. K.69, Buchireddipalem, Nellore District, Andhra Pradesh for the purposes of the said proviso.

[No. 8/145/70-PF.II-(ii).]

का० आ० ३९१—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ (१९५२ का १९) की धारा ६ के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्वारा कि बुचिरेडडीपलेम कोऑपरेटिव रूरल बैंक लिमिटेड, सं० के० ६९, बुचिरेडडीपलेम, नैल्लोर जिला, आन्ध्रप्रदेश नामक स्थापन को प्रथम जनवरी, १९७० से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[संख्या ८/१४५/७०-पी०एफ० २(ii)]

S.O. 392.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Durlabh Metal Industries Private Limited, Howrah Industrial Estate Shed No. L-26, 36 and 37 P.O. Baltikuri, District Howrah, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1969.

[No. 8/166/70/PF.II.]

का० आ० ३९२—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स दुर्लभ मेटल इंडस्ट्रीज प्राइवेट, लिमिटेड हावड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट शेड सं० एल० २६, ३६ और ३७ डाकघर बल्टीकुरी, जिला हावड़ा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ (१९५२ का १९) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा १ की उपधारा (४) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना १९६९ की जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० ८/१६६/७० पी०फ०]

S.O. 393.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mysore Kirloskar Employees' Co-operative Society Limited, Yantrapur Post Office Harihar, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1969.

[No. 8/94/69-PF.II(i).]

का० आ० 393 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स मसूर किलोस्कर एम्प-
लायीज कोओपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, यन्त्रपुर, डाकघर हरिहर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक
और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,
1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1969 की जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[संख्या 8/94/168-पी एफ०-2(ii)]

S.O. 394.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st June, 1969 the establishment known as Messrs Mysore Kirloskar Employees' Co-operative Society Limited, Yantrapur Post Office Harihar, for the purposes of the said proviso.

[No. 8/94/69-PF.II(ii).]

का० आ० 394 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के
प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच
नेने के पश्चात् एत द्वारा मेसर्स मसूर किलोस्कर एम्पलायीज कोओपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, यन्त्रपुर
डाकघर हरिहर नामक स्थापन को प्रथम जून, 1969 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट
करती है ।

[सं० 8/94/69-पी० एफ०-2(ii)]

S.O. 395.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Superb Corporation, Ram Mandir Road, Goregaon (West), Bombay-62 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1969.

[No. 8/24/70/PF.II.].

का० आ० 395 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स सुपर्व
कारपोरेशन, राम मन्दिर रोड, गोरेगांव (पश्चिमी) मुंबई-62 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक
और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,
1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का योग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1969 के अगस्त के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या 8/24/70-पी० एफ० 2]

S.O. 396.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hindustan Coconut Oil Mill, Post Sainthia, District Birbhum, West Bengal have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1969.

[No. 8/168/70/PF.II.]

का० प्रा० 396^व यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स हिन्दुस्तान कोकोनट आयल मिल, डाकघर सेन्थिया, जिला बीरभूम, पश्चिमी बंगाल नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1969 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या 8/168/70-पी० एफ० 2]

New Delhi, the 18th January 1971

S.O. 397.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour No. S.R.O. 908 dated the 7th May, 1953, the Central Government hereby appoints the 24th January, 1971, as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 thereof which have already been brought into force), Chapter V and Chapter VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 87, 79 and 81 thereof which have already been brought into force), of the said Act shall come into force in the following areas of the State of Punjab, namely:—

I. (i) The areas comprised within the limits of Abdullapur Notified Area Committee.

(ii) The Areas comprised within the limits of Jagadhri Municipal Committee.

(iii) The Revenue villages of—

- (a) Abdullapur.
- (b) Mamida.
- (c) Habipur.
- (d) Garhi.
- (e) Chandpur.
- (f) Govindpur.
- (g) Moond Majra.
- (h) Hamida.
- (i) Jagadhri.
- (j) Garhi Mondo.
- (k) Tejli.
- (l) Govindpura.

II. (i) The Areas comprised within the limits of Ambala Municipal Committee.

(ii) The Areas comprised within the limits of Ambala Cantonment Board.

(Hi) The Revenue villages of—

- (a) Shahpur.
- (b) Kuldip Nagar.
- (c) Manchanda.

...

III. (i) The Areas comprised within the limits of Ludhiana Municipal Committee.

(ii) The Revenue villages of—

- (a) Taraf Burara.
- (b) Nur Bhaini.
- (c) Taraf Piru Banda.
- (d) Taraf Saidian.
- (e) Dholewal.
- (f) Sher Pur Khurd.
- (g) Taraf Qazi.
- (h) Gill.

IV. (i) The Areas comprised within the limits of Jullunder Municipal Committee.

(ii) The Areas comprised within the limits of Jullunder Cantonment Board.

(iii) The Revenue villages of—

- (a) Dokoha.
- (b) Reru.
- (c) Butan.
- (d) Maksoodpur Had Bast No. 317.

V. (i) The Areas comprised within the limits of Amritsar Municipal Committee.

(ii) The Areas comprised within the limits of Chhehrata Notified Area Committee.

(iii) The Revenue villages of—

- (a) Vijaynagar.
- (b) Tund Pain.
- (c) Verka.
- (d) Mustafabad.
- (e) Tung Bala.
- (f) Moghampur.
- (g) Vallah.

VI. (i) The Areas comprised within the limits of Batala Municipal Committee.

(ii) The Revenue villages of—

- (a) Falzpur.
- (b) Punder.
- (c) Kotla Nawab.
- (d) Batala West.

VII. The Areas comprised within the limits of Bhiwani Municipal Committee.

[No. 13/17/68-HL.]

DALJIT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1971

एत० प्री० 397.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 908, तारीख 7 मई, 1953 को अधिष्ठात करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 24 जनवरी 1971 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय IV (उसकी धारा 44 और 45 के सिवाय जो कि पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है), अध्याय V और अध्याय VI (धारा 76 की उपधारा

(1) और 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जोकि पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) पंजाब राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

I (i) अम्बुल्लापुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की सीमाओं में आने वाले क्षेत्र ।

(ii) जगाधारी नगरपालिका समिति की सीमाओं में आने वाले क्षेत्र ।

(iii) (क) अम्बुल्लापुर

(ख) ममीदा

(ग) हबीपुर

(घ) गढ़ी

(ङ) चान्दपुर

(च) गोविन्दपुरी

(छ) मंद माजरा

(ज) हमीदा

(झ) जगावरी

(ञ) गढ़ी मोड़ो

(ट) तेजली

(ठ) गोविन्दपुरा

के राजस्व ग्राम

II (i) अम्बाला नगर पालिका समिति की सीमाओं में आने वाले क्षेत्र ।

(ii) अम्बाला छावनी बोर्ड की सीमाओं में आने वाले क्षेत्र ।

(iii) (क) शाहपुर

(ख) कुलदीप नगर

(ग) मंचन्दा

के राजस्व ग्राम

III (i) लुधियाना नगरपालिका समिति की सीमाओं में आने वाले क्षेत्र ।

(ii) (क) तारफ बरारा

(ख) नरमेनी

(ग) तारफ पीरू बन्दा

(घ) तारफ सेयदन

(ङ) धोलेवल

(च) शरपुर खुर्द

(छ) तारफ काजी

(ज) गिल

के राजस्व ग्राम

IV (i) जलन्धर नगरपालिका समिति की सीमाओं में आने वाले क्षेत्र ।

(ii) जलन्धर छावनी बोर्ड की सीमाओं में आने वाले क्षेत्र ।

(क) दोकोहा

- (ख) रेह
- (ग) बूटन
- (घ) मकसरपुर

के राजस्व ग्राम

- V (i) अमृतसर नगरपालिका समिति की सीमाओं में आने वाले क्षेत्र
 (ii) छहराता अधिसूचित क्षेत्र समिति की सीमाओं में आने वाले क्षेत्र ।
 (iii) (क) विजय नगर
 (ख) टूंडपेन
 (ग) बेरका
 (घ) मस्तफाबाद
 (ङ) टूंगबाला
 (च) मोगमपुर
 (छ) बल्लाह

के राजस्व ग्राम

- VI (i) बटाला नगर पालिका समिति की सीमाओं में आने वाले क्षेत्र ।
 (ii) (क) फेजपुर
 (ख) पन्देर
 (ग) कोटला नवाण
 (घ) बटाला पश्चिम

के राजस्व ग्राम

- VII भिवानी नगरपालिका समिति की सीमाओं में आने वाले क्षेत्र ।

[सं० फा० 13/17/69-एच० आई०]

दलजीत सिंह, अवसर सचिव ।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 14th January 1971

S.O. 398.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Victory Colliery (M. J. Group) of Messrs Coal Products Private Limited, Post Office Nutandanga, District Burdwan and their workmen which was received by the Central Government on the 12th January, 1971.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

REFERENCE No. 56 OF 1970

PARTIES :

Employers in relation to the management of Victory Colliery (M. J. Group)
 of Messrs Coal Products Private Limited,

AND

Their workmen.

PRESENT:

Mr. B. N. Banerjee.—Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers—Sri Sambhu Nath Jain.

On behalf of Workmen—Sri Bishnu Malkhandy, Vice-President, Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj.

STATE: West Bengal.

INDUSTRY: Coal Mines.

AWARD

This reference is being taken up out of turn on the joint prayer of both the parties.

2. By Order No. 6/40/70-LR. II, dated October 28, 1970, the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred the following dispute between the employers in relation to the management of Victory Colliery (M. J. Group) of Messrs Coal Products Private Limited and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:

“Whether the management of Victory Colliery (M. J. Group) of Messrs Coal Products Private Limited, Post Office Nutandanga, District Burdwan was justified in dismissing Shri S. M. Ghosh, Overman from the 2nd January, 1970. If not, to what relief is the workman entitled?”

3. I need not adjudicate the dispute on evidence. The parties have settled the dispute and in token thereof filed a petition of settlement embodying the terms of compromise. Now, that the parties have settled their dispute, I pass an award in terms of the settlement. Let the petition of settlement form part of this award.

(Sd.) B. N. BANERJEE,
Presiding Officer.

Dated, January 2, 1971

BEFORE SHRI BINAYAK BANERJEE, PRESIDING OFFICER, CENTRAL
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Dated 29th December 1970

In the matter of an Industrial Dispute

BETWEEN

The Employers in relation to the Victory Colliery (M. J. Group) of M/s. Coal Products Private Ltd, P.O. Natundanga, Dist. Burdwan.

AND

Their workmen, represented by Colliery Mazdoor Sabha, P.O. Raniganj and Dist Burdwan.

AND

In the matter of Ref. No 56 of 1970.

Most respectfully Sheweth,

The abovementioned employers and the above union representing the workmen have come to a settlement in the following terms and manners in the above mentioned reference.

(1) That, Shri S. M. Ghosh, Overman, shall be reinstated on and from 1st January 1971 with continuity of his service.

(2) That, Shri S. M. Ghosh, however, shall get 50 per cent of his total wages and other benefits for the period of his unemployment from 2nd January, 1970 till his date of reinstatement.

(3) That, it is agreed by the management that the payment of item (2) shall be made on 30th December, 1970 at the Colliery office.

(4) That, this resolves the disputes and neither party will agitate about this dispute any further to any court of law.

(5) That all legal dues prior to 2nd January, 1970 shall be paid on and before 15th January 1971 to the workman.

Therefore, both the employers and the union submit that the Hon'able Tribunal will kindly give an award in the light of this petition and for this act of kindness both the management and the union shall remain obliged.

(Sd.) ROBIN CHATTERJEE

Representing the Workmen:

Dated the 29th December, 1970

(Sd.) M. K. NEOGI,
Representing the Employers.

[No. 6/40/70-LRII.]

S.O. 399.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Victory Colliery (M. J. Group) of Messrs Coal Products Private Limited, Post Office Nutandanga, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th January, 1971.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA.

REFERENCE No. 51 OF 1970

PARTIES:

Employers in relation to the Victory Colliery (M. J. Group) of Messrs Coal Products (Private) Limited,

AND

Their workmen.

PRESENT:

Mr. B. N. Banerjee.—Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers—Sri Sambhu Nath Jain.

On behalf of Workmen—Sri Robin Chatterjee, General Secretary, Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj.

STATE: West Bengal

INDUSTRY: Coal Mines

AWARD

By Order No. 6/37/70-LRII, dated October 17, 1970, the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred the following dispute between the employers in relation to the Victory Colliery (M. J. Group) of Messrs Coal Products (Private) Limited and their workmen, for adjudication, to this Tribunal, namely:

“Whether the management of Victory Colliery (M. J. Group) of Messrs Coal Products Private Limited, Post Office Nutandanga, District Burdwan was justified in terminating the services of Shri Dilip Ghosh, Clerk of the colliery, from the 1st April, 1970? If not, to what relief the workman is entitled?”

2. I need not adjudicate the dispute on evidence. The parties have settled the dispute and in token thereof filed a joint petition of settlement. Now, that there is no further dispute between the parties, I pass an award in terms of the settlement. Let the petition of settlement form part of this award. Be it recorded that the terms contained paragraphs 1, 2 of the petition of settlement have already been implemented.

(Sd.) B. N. BANERJEE,
Presiding Officer.

Dated, January 2, 1971.

BEFORE SHRI BINAYAK BANERJEE, PRESIDING OFFICER, CENTRAL
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA.

The 29th December, 1970

In the matter of an Industrial Dispute.

BETWEEN

The Employers in relation to Victory Colliery (M. J. Group) of M/s. Coal Products Private Ltd., P.O. Nutandanga, Dist., Burdwan.

AND

Their workmen, represented by Colliery Mazdoor Sabha, (CITU) P.O. Raniganj and Dist., Burdwan.

AND

In the matter of Ref., No. 51 of 1970.

Most respectfully Sheweth,

The abovementioned employers and the above union representing workmen have come to a settlement in the following terms and manners in the above mentioned reference.

(1) That, Shri Dilip Ghosh, clerk, shall be reinstated on and from 1st January, 1971, with continuity of his service.

(2) That, Shri Dilip Ghosh, however, shall get 50 per cent of his total wages and other benefits for the period of his unemployment from 1st April, 1970 till his date of reinstatement.

(3) That, it is agreed by the management that the payment if item (2) shall be made on 30th December, 1970, at the Colliery office.

(4) That, this resolves the disputes and neither party will agitate about this dispute any further to any court of law.

(5) That all legal dues due to workman prior to 1st April, 1970, shall be paid on or before 15th January, 1971.

Therefore, both the employers and the union submit that the Hon'ble Tribunal will kindly give an award in the light of this petition and for this act of kindness both the management and the union shall remain obliged.

(Sd.) M. K. NEOGI,
Representing Employers.

(Sd.) ROBIN CHATTERJEE,
Representing the workmen.
Dated, the 29th December, 1970.

[No. 6/37/70-LRIL.]

S.O. 400.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur. In the industrial dispute between the employers in relation to the Management of Bhadra Colliery of Messrs Rewa Mining Company Limited, Post Office Kotma, District Shahdol (Madhya Pradesh) and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th January, 1971.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
JABALPUR

Dated December 21, 1970

PRESENT:

Shri M. Chandra, Presiding Officer.

CASE No. CGIT/LC(R) (10) OF 1970

PARTIES:

Employers in relation to M/s. Bhadra Colliery of Rewa Mining Colliery Ltd. Bhadra Colliery, P.O. Kotma, Distt. Shahdol (M.P.)

Versus

Their workmen.

APPEARANCES :

For employers—Sri S. K. Katyal.

For workmen—Sri G. C. Jaiswal.

INDUSTRY: Coal Mine.

DISTRICT: Shahdol (M.P.)

AWARD

This is a reference under Sec. 10 of the Industrial Disputes Act. By the order No. 1/28/70-LRII, dated 7th September, 1970 the Government of India referred a dispute between the management of Bhadra Colliery of M/s Rewa Mining Colliery Ltd. and their workmen to this Tribunal. The subject matter of the dispute as given in the schedule to the order of reference is as under:—

"Whether the management of Messrs Rewa Mining Company Limited, Bhadra Colliery, Post Office Kotma, District Shahdol (Madhya Pradesh) is justified in not introducing the wage structure and other benefits in accordance with the recommendations of the Central Wage Board for Coal Mining Industry as accepted by the Government of India in their resolution No. WB. 16(5)/66, dated the 21st July, 1967 in respect of Variable Dearness Allowance and grant of annual increments 15th August, 1968 and 15th August, 1969? If not, to what relief are the workmen entitled and from what date?"

The failure report of the Asstt. Labour Commissioner, Shahdol dated 1st May, 1970 gives in brief the dispute between the management and the workmen. The case of the Union was that the management of M/s. Rewa Mining Company Ltd. had not implemented the recommendations of the Central Wage Board for Coal Mining Industry although they had been accepted and implemented by other collieries. The Union insisted that the management should implement the Central Wage Board recommendations and pay the arrears to the workers concerned.

The reply on behalf of the management was that Bhadra Colliery was a very small mine, that their production had gone down to about 2000 tonnes per month and that they were facing great financial difficulties in running the mine and meeting the day-to-day expenditure. According to the management the mine was being run only with a view to keep the workers employed and Sri P. N. Singh, Secretary, Colliery Mazdoor Union, had signed a settlement on 15th October, 1968 with the management wherein the wages of the piece-rated miners and daily rated and monthly rated workers had been increased. The management further alleged that the settlement was valid for a period of two years with effect from 15th October, 1968, and that the alternative would be to close down the colliery resulting in unemployment and great hardship to about 300 workers and their family.

Parties have now entered into a compromise to the effect that the management agrees to introduce wage structure in accordance with the recommendations of the Central Wage Board for Coal Mining Industry, as accepted by the Government of India, with effect from 15th May, 1970 and to pay Variable Dearness Allowance also at Rs. 1.30 P. per day from 15th May, 1970. The management then says that they have already started paying wages at new rates and the V.D.A. at the rate of Rs. 1.30 P. per day with effect from 10th August, 1970. These rates have been accepted by the workmen who also confirmed the payment. Regarding the arrears on account of the difference of wages for the period 15th May, 1970 to 9th August, 1970 it has been agreed that the management will pay the same on or before 30th June, 1971. As for the grant of annual increments on 15th August, 1968 and 15th August, 1969 the management has agreed to give one increment with effect from 15th August, 1970 and the agreement says that this issue stands settled. It is further agreed between the parties that this settlement shall be taken as full implementation of the recommendations of the Central Wage Board for Coal Mining Industry as accepted by the Government of India in their Resolution No. WB16(5)/66, dated 21st July, 1967. The compromise is reasonable and is accepted. The award is made in terms of the compromise which shall form part of the award. Let the award be sent to the Government.

(Sd.) M. CHANDRA,
Presiding Officer.
21-12-1970.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-
LABOUR COURT, JABALPUR

IN THE MATTER OF REFERENCE No. CGIT/LC/(R) (10)/70

BETWEEN

The employers in relation to Bhadra Colliery of M/s. Rewa Mining Company Ltd., Post Office Kotma, Distt. Shahdol, Madhya Pradesh (M.P.)

AND

Their workmen as represented by the General Secretary, Colliery Mazdoor Union, Post Office, Birsinghpur Pali, District Shahdol, Madhya Pradesh.

Prayer for accepting Settlement and passing Awards

May it please the Hon'ble Tribunal,

That both the management and the workmen have arrived at the following mutual settlement in respect of the matter under reference.

Terms of Settlement

1. The management agrees to introduce wage structure in accordance with the recommendations of the Central Wage Board for Coal Mining Industry as accepted by the Government of India, with effect from 15th May, 1970.

2. As regards the variable dearness allowance the management agrees to pay the same @ 1.30 p. per day from 15th May, 1970.

3. The management has already started paying wages at new rates and the V.D.A. at the rate of Rs. 1.30 p. per day with effect from 10th August, 1970. The workmen accept the rates and confirm the payment.

4. As regards arrears on account of difference of wages for the period from 15th May 1970 to 9th August 1970 it is hereby agreed that the management will pay the same on or before 30th June, 1971.

5. As regards to grant of annual increment on 15th August, 1960 and 15th August, 1969 the management agrees to give one increment with effect from 15th August, 1970 and this issue stands settled.

6. This settlement shall be taken as full implementation of the recommendations of the Central Wage Board for Coal Mining Industry as accepted by the Government of India in their resolution No. WB16(5)/66, dated the 21st July, 1967.

Prayer

The parties pray to the Hon'ble Tribunal to accept the settlement and to pass it as an award.

Representing the Workmen:

(Sd.) G. C. JAISWAL,
General Secretary,
Colliery Mazdoor Union,
P.O. Birsinghpur Pali,
Distt. Shahdol (M.P.)

Representing the Employers:

(Sd.) S. K. KATYAL,
Administrative Officer,
Rewa Mining Co. Ltd.,
-P.O. Kotma, Distt. Shahdol (M.P.)

PART OF AWARD

(Sd.) M. CHANDRA,
Presiding Officer.
21-12-1970.

Jabalpur, dated 21st December, 1970.

[No. 1/28/70-LRII.]

S.O. 401.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bankoli Colliery, Post Office Ukhra, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th January, 1971.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

REFERENCE No. 50 OF 1970

PARTIES:

Employers in relation to the management of Bankola Colliery,

AND

Their workmen.

PRESENT:

Mr. B. N. Banerjee, Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers—Sri S. B. Sanyal, Legal Adviser.

On behalf of Workmen—Sri R. Singh, President, Bankola Workers Union.

STATE: West Bengal

INDUSTRY: Coal Mines

AWARD

By Order No. 6/8/70-LR-II, dated October 14, 1970, the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred the following dispute between the employers in relation to the management of Bankola Colliery and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:—

“Whether the management of Bankola Colliery, Post Office Ukhra, District Burdwan was justified in dismissing the following workmen from the date shown against each:—

1. Shri Adhemo Sasmal, Wagon Loader, 28-7-1969,
2. Shri Saitu Khuntia, Wagon Loader, 28-7-1969
3. Shri Sanchan Pradhan, Wagon Loader 15-7-1969

If not, to what relief are they entitled?”

2 Both the parties filed their respective written statements. Some evidence, both documentary and oral, was also recorded. I was thereafter not required to go further into the dispute because the parties settled the dispute amicably and filed signed terms of settlement before this Tribunal to the following effect:

- (a) that for the sake of maintaining industrial peace and good relation with the workmen the present dispute be no further pursued.
- (b) that the management will permit the three wagon loaders named in the order of Reference to work as casual workmen at Bankola colliery for the present.
- (c) that the first three vacancies, occurring amongst the category of permanent wagon loaders, will be filled up one after another by the three concerned workmen named in the order of reference, if available at the colliery on the date of vacancy aforesaid.
- (d) that an award be made in terms of the above settlement.

3. Since the parties have settled their dispute on the terms quoted above, pass an award in terms thereof.

(Sd.) B. N. BANERJEE,
Presiding Officer.

Dated, December 31, 1970.

[No. 6/8/70-LR.II.]

KARNAIL SINGH, Under Secy.

(Department of Labour and Employment)
[Office of the Chief Labour Commissioner (Central)]

ORDERS

New Delhi, the 12th January 1971

S.O. 402.—Whereas an application has been made under section 19(b) of the Payment of Bonus Act, 1965 by Messrs Tiffin's Barytes Asbestos & Paints Ltd. (employer) in relation to their establishments mentioned in the Schedule below for extension of the period for the payment of bonus to their employees for the accounting year ending on 31st March, 1970.

And whereas being satisfied that there are sufficient reasons to extend the time I have, in exercise of the powers conferred on me by the proviso to clause (b) of Section 19 of the said Act read with the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. WB20(42)/65, dated the 28th August, 1965, passed order on 11th January, 1971 extending the period for payment of the said bonus by the said employer by two months (i.e. upto 31st January, 1971) from the last date for payment of bonus under clause (b) of Section 19 of the Act.

Now, this is published for information of the employer and all the employees of the said establishment.

THE SCHEDULE

Name and address of the employer(s).	Establishment(s)
M/s. Tiffin's Barytes Asbestos & Paints Ltd., Andhra Chamber Building, 272/273, Angappa Naiek Street, P.B. No. 73, Madras-1.	—

[No. BA-6(28)/70-LS.I.]

(श्रम और रोजगार विभाग)

मुख्य श्रम आयुक्त (कन्द्रीय) का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1971

एस० ओ० 402.—यतः मैसर्स टीफीन बराइट्स एस्बेस्टोज एण्ड पेंट्स लिमिटेड (नियोजक) ने नीचे की अनुसूची में वर्णित अपने स्थापनों के सम्बन्ध में 31-3-70 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए अपने कर्मचारियों को बोनस के संदाय की कालावधि को बढ़ाने के लिए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 19(ख) के अधीन आवेदन दिया है।

और यतः यह समाधान हो जाने पर कि समय बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण हैं, मैंने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० डब्ल्यू बी०-20(42)/65 तारीख 28 अगस्त, 1965 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 11-1-71 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त बोनस के संदाय की कालावधि को अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के अधीन बोनस के संदाय को अंतिम तारीख से 2 महीने (अर्थात् 31-1-71 तक) बढ़ाने का आदेश दे दिया है।

अब इसे उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

अनुसूची

नियोजक/नियोजकों का नाम और पता

स्थापन

मैसर्स टीफन बेराइट्स एसबैस्टस एण्ड पेन्ट्स (लि०), आंध्रा
चैम्बर बिल्डिंग 272/273, ए० एन० स्ट्रीट मद्रास-1

[सं० बी० ए० 6(28)/70-एम एस-1]

New Delhi, the 14th January 1971

S.O. 403.—Whereas an application has been made under section 19(b) of the Payment of Bonus Act, 1965 by Messrs Parasea Collieries Ltd. (employer) in relation to their establishments mentioned in the Schedule below for extension of the period for the payment of bonus to their employees for the accounting year ending on 31st December, 1969.

And whereas being satisfied that there are sufficient reasons to extend the time I have, in exercise of the powers conferred on me by the proviso to clause (b) of Section 19 of the said Act read with the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. WB.20(42)/65, dated the 28th August 1965, passed order on 14th January 1971 extending the period for payment of the said bonus by the said employer by five months (i.e. up to 31st January, 1971), from the last date for payment of bonus under clause (b) of Section 19 of the Act.

Now this is published for information of the employer and all the employees of the said establishment.

SCHEDULE

Name and address of the employer(s).

Establishment(s)

M/s. Parasea Collieries Ltd., Parasea Colliery, P.O. Kajoragram, Distt. Burdwan, West Bengal.

[No. BA-5(19)/70-LS.I.]

O. VENKATACHALAM,
Chief Labour Commissioner (Central).

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1971

एस० प्रो० 403.—यतः मैसर्स पारासिया कोइलरी लि. (नियोजक) ने नीचे की अनुसूची में वर्णित अपने स्थापनों के सम्बन्ध में 31-12-69 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए अपने कर्मचारियों को बोनस के संदाय की कालावधि को बढ़ाने के लिए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 19(ख) के अधीन आवेदन दिया है।

और यतः यह समाधान हो जाने पर कि समय बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण हैं, मैंने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचनाएं सं० डब्ल्यू बी-20(42)/65 तारीख 28 अगस्त, 1965 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए 14-1-71 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त बोनस के संदाय की कालावधि को अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के अधीन बोनस के संदाय को अंतिम तारीख से 5 महीने (अर्थात् 31-1-71 तक) बढ़ाने का आदेश दे दिया है।

अब इसे उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

अनुसूची

नियोजक/नियोजकों
का नाम और पता

स्थापन

मैसर्स पारसिया कोइलरी लि. पारसिया कोइलरी काजोरा ग्राम
जि. वर्दवान, बैस्ट बंगाल

[सं० बी० ए० 5 (19) 70-एल० एस० I]

श्री० बेंकटाचलम,
मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)।

(Department of Rehabilitation)

(Office of the Chief Settlement Commissioner)

New Delhi, the 12th January 1971

S.O. 404.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-Section (2) of Section 16 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints for the Union Territory of Delhi, Shri Harish Chander Chaudhary Managing Officer in the office of the Regional Settlement Commissioner, New Delhi as Managing Officer for the custody, management and disposal of compensation pool with immediate effect.

[No. 7/13/ARG-62.]

JANKI NATH,
Settlement Commissioner (C) & Ex-Officio Under Secy.

(पुनर्वास विभाग)

(मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त का कार्यालय)

नई दिल्ली, तारीख 12 जनवरी, 1971

एस० ओ० 404.—विस्थापित व्यक्ति (मुआविजा तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 (1954 के 44) के अंश (ए) के भाग 16 के उपभाग (2) की प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने श्री हरीश चन्द्र चौधरी को जो कि प्रादेशिक बन्दोबस्त आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली में प्रबन्ध अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं तत्काल ही संघीय क्षेत्र दिल्ली के लिये प्रबन्ध अधिकारी नियुक्त किया है ताकि वे अभिरक्षक, प्रबन्ध तथा उन सम्पत्तियों का निपटारा कर सकें जो कि प्रतिकर कोष के अन्तर्गत आती है।

[संख्या 7/13/ए० आर० जी-62]

जानकी नाथ

बन्दोबस्त आयुक्त (सी)

तथा

भारत सरकार के पदेन

अवर सचिव।

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS

(Department of Mines and Metals)

New Delhi, the 12th January 1971

S.O. 405.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines No. S.O. 2565, dated the 21st August 1965, made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired:

- (i) Lands measuring 235.00 acres in villages Manidi, Garbhudih, Bardubhi Baludih, Dubrajpur and Jatudih; and
- (ii) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in lands measuring 40.00 acres in villages Garbhudih, Baludih, Dubrajpur, Bardubhi and Jatudih, in the District, Dhanbad.

And whereas Sarvashri Keshwa Singh and Sahdeo Mosif were found as persons interested under section 13 of the said Act, in accordance with the authentication by the State Government authorities and accordingly compensation for an area 0.81 acres of the said acquisition was assessed in their favour;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute as to the sufficiency of amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by the persons interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Shri Rabneshwar Prasad Sinha, Additional Judicial Commissioner, Ranchi, for the purpose of determining the amount of compensation payable to the persons interested.

[No. F. C3-5(9)/70.]

पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय

(खान और धातु विभाग)

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1971

का० आ० 405.—यतः कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन भारत सरकार के भूतत्पूर्व इस्पात और खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2565 तारीख 21 अगस्त, 1965 के अनुसारण में केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित का अर्जन किया है :—

- (i) मनीदी, गरबूडीह, बारदुभी, बालुडीह, डुबराजपुर, और जातुडीह ग्रामों में 235.00 एकड़ माप की भूमि; और
- (ii) धनबाद जिले में गरबूडीह, बालुडीह, डुबराजपुर, बारदुभी और जातुडीह ग्रामों में 40.00 एकड़ माप की भूमि में, खनिजों के खनन, खदान क्रिया, बोर करने, खोदने के लिए और उनकी तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, कार्य करने और ले जाने के अधिकार।

और यतः राज्य सरकार प्राधिकारियों के अधिप्रमापीकरण के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन सर्वश्री केशव सिंह और सहदेव मौसिफ हितबद्ध व्यक्ति पाये गये थे और तदनुसार 0.81 एकड़ क्षेत्र के उक्त अर्जन के लिए प्रतिकर उनके पक्ष में निर्धारित किया गया था;

और यतः प्रस्थापित प्रतिकर की राशि की पर्याप्तता के बारे में विवाद होने से उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की राशि करार द्वारा नियत नहीं की जा सकी; और इस प्रकार प्रस्थापित राशि हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा सविरोध ही स्वीकार की गई है;

अतः, अब कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती हुए, केन्द्रीय सरकार हितबद्ध व्यक्तियों को सदेय प्रतिकर की राशि को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा एक अधिकरण को गठित करती है जिसमें श्री रबनेश्वर प्रसाद सिन्हा, अपर न्यायिक आयुक्त, रांची होंगे।

[सं० फा० को० 3-5(9)/70]

S.O. 406.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines No. S.O. 2565, dated the 21st August, 1965, made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired:

- (i) Lands measuring 235.00 acres in villages Manidi, Garbhudih, Bardubhi Baludih, Dubrajpur and Jatudih; and
- (ii) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in lands measuring 40.00 acres in villages Garbhudih, Baludih, Dubrajpur, Bardubhi and Jatudih, in the District Dhanbad.

And whereas Sarvashri Jyoti Mosif, Bhuneshwar Mosif, Baghu Mosif, and Pramod Mosif were found as persons interested under section 13 of the said Act, in accordance with the authentication by the State Government authorities and accordingly compensation for an area 0.30 acres of the said acquisition was assessed in their favour;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute as to the sufficiency of amount of the compensation offered and the amount so offered has been accepted by the persons interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1937, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Shri Rabneshwar Prasad Sinha, Additional Judicial Commissioner, Ranchi, for the purpose of determining the amount of compensation payable to the persons interested.

[No. F.C3-5(9)/70.]

फा० ग्रा० 406.—यतः कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या फा० ग्रा० 2565 तारीख 21 अगस्त, 1965 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित का अर्जन किया है :—

- (i) मनीदी, गरबूडीह, बारदुभी, बालुडीह, डुबराजपुर और जालुडीह ग्रामों में 235.00 एकड़ माप की भूमि; और
- (ii) धनबाद जिले में गरबूडीह, बालुडीह, डुबराजपुर, बारदुभी और जालुडीह ग्रामों में 40.00 एकड़ माप की भूमि में, खनिजों के खनन, खदान क्रिया, बोर करने, खोदने के लिए और उनकी तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, कार्य करने और ले जाने के अधिकार।

और यतः राज्य सरकार प्राधिकारियों के अधिप्राप्तीकरण के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन सर्वश्री ज्योति मौसिफ, भूनेश्वर मौसिफ, भगु मौसिफ और प्रमोद मौसिफ हितबद्ध व्यक्ति पाये गये थे और तदनुसार 0.30 एकड़ क्षेत्र के उक्त अर्जन के लिए प्रतिकर उनके पक्ष में निर्धारित किया गया था।

और यतः प्रस्थापित प्रतिकर की राशि की पर्याप्तता के बारे में विवाद होने से उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की राशि करार द्वारा नियत नहीं की जा सकती; और इस प्रकार प्रस्थापित राशि हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा सविरोध ही स्वीकार की गई है;

अतः, अब कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की राशि को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा एक अधिकरण को गठित करती है जिसमें श्री रबनेश्वर प्रताप सिन्हा, अपर न्यायिक आयुक्त, रांची होंगे।

[सं० फा० को० 3-5(9)/70]

S.O. 407.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines No. S.O. 2565, dated the 21st August, 1965, made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired:

- (i) Lands measuring 235.00 acres in villages Manidi, Garbhudih, Bardubhi, Baludih, Dubrajpur and Jatudih; and
- (ii) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in lands measuring 40.00 acres in villages Garbhudih, Baludih, Dubrajpur, Bardubhi and Jatudih, in the District Dhanbad.

And whereas Sarvashri Bijoy Singh, Haldhar Singh, Mahabir Singh, and Srimati Shobha Kumari, w/o Nanku Singh were found as persons interested under section 13 of the said Act in accordance with the authentication by the State Government authorities and accordingly, compensation for an area 4.04 acres of the said acquisition was assessed in their favour;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute as to the sufficiency of amount of the compensation offered and the amount so offered has been accepted by the persons interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Shri Rabneshwar Prasad Sinha, Additional Judicial Commissioner, Ranchi, for the purpose of determining the amount of compensation payable to the persons interested.

[No. F.C3-5(9)/70.]

का० आ० 407.—यतः कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2565 तारीख 21 अगस्त, 1965 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित का अर्जन किया है :—

- (i) मनीदी, गरबूडीह, बारदुभी, बालुडीह, डुबराजपुर और जातुडीह ग्रामों में 235.00 एकड़ माप की भूमि; और
- (ii) धनबाद जिले में गरबूडीह, बालुडीह, डुबराजपुर, बारदुभी और जातुडीह ग्रामों में 40.00 एकड़ माप की भूमि में, खनिजों के खनन, खदान क्रिया, बोर करने, खोदने के लिए और उनकी तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, कार्य करने और ले जाने के अधिकार।

और यतः राज्य सरकार के प्राधिकारियों के अधिप्रमापीकरण के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन सर्वश्री विजय सिंह, हलधर सिंह, महावीर सिंह और श्रीमती शोभा कुमारी पत्नी नानकु सिंह हितबद्ध व्यक्ति पाये गये थे और तदनुसार 4.04 एकड़ क्षेत्र के उक्त अर्जन के लिए प्रतिकर उनके पक्ष में निर्धारित किया गया था;

और यतः प्रस्थापित प्रतिकर की राशि की पर्याप्तता के बारे में विवाद होने से उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की राशि करार द्वारा नियत नहीं की जा सकी; और इस प्रकार प्रस्थापित राशि हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा सविरोध ही स्वीकार की गई है;

अतः, अब कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की राशि को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा एक अधिकरण को गठित करती है जिसमें श्री रबनेश्वर प्रसाद सिन्हा, अपर न्यायिक आयुक्त, रांची होंगे।

[सं० फा० को० 3-5(9)/70]

S.O. 408.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines No. S.O. 2565, dated the 21st August, 1965, made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired:

- (i) Lands measuring 235.00 acres in villages Manidi, Garbhudih, Bardubhi Baludih, Dubrajpur and Jatudih; and
- (ii) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in lands measuring 40.00 acres in villages Garbhudih, Baludih, Dubrajpur, Bardubhi and Jatudih, in the District Dhanbad.

And whereas Sarvashri Maharaj Singh, Jhalu Singh and Shrimati Butan Devi w/o Dari Sai were found as persons interested under section 13 of the said Act, in accordance with the authentication by the State Government authorities and accordingly compensation for an area of 0.53 acres of the said acquisition was assessed in their favour;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute as to the sufficiency of amount of the compensation offered and the amount so offered has been accepted by the persons interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Shri Rabneshwar Prasad Sinha, Additional Judicial Commissioner, Ranchi, for the purpose of determining the amount of compensation payable to the persons interested.

[No. F.C.3-5(9)/70.]

का० आ० 408.—यतः कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2565 तारीख 21 अगस्त, 1965 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित का अर्जन किया है :—

- (1) मनीदी, गरबूडीह, बारदुभी, बालुडीह, डुबरापुर और जातुडीह ग्रामों में 235.00 एकड़ माप की भूमि ; और
- (2) धनबाद जिले में गरबूडीह, बालुडीह डुबराजपुर, बारदुभी और जातुडीह ग्रामों में 40.00 एकड़ माप की भूमि में खनिजों के खनन, खादान क्रिया, बोर करने, खोदने के लिए उन की तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, कार्य करने और ले जाने के अधिकार।

और यतः राज्य सरकार प्राधिकारियों के अधिग्रहणीकरण के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन सर्व श्री महाराज सिंह, जालू सिंह और श्रीमती बृटन देवी पत्नी दारी साय हितबद्ध व्यक्ति पाए गए थे और तदनुसार 0.53 एकड़ क्षेत्र के उक्त अर्जन के लिए प्रतिकर उनके पक्ष में निर्धारित किया गया था।

और यतः प्रस्थापित प्रतिकर की राशि की पर्याप्तता के बारे में विवाद होने से उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की राशि करार द्वारा नियत नहीं की जा सकी ; और इस प्रकार प्रस्थापित राशि हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा सविरोध ही स्वीकार की गई है ;

अतः, अब कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957, की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की राशि को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा एक अधिकरण को स्थापित करती है जिसमें श्री रबनेश्वर प्रसाद सिन्हा, अपर न्यायिक आयुक्त, रांची होंगे।

[सं० फा० को० 3-5-(9)/70]

S.O. 409.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines No. S.O. 2565, dated the 21st August, 1965, made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired:

- (i) Lands measuring 235.00 acres in villages Manidi, Garbhudih, Bardubhi, Baludih, Dubrajpur and Jatudih; and
- (ii) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in lands measuring 40.00 acres in villages Garbhudih, Baludih, Dubrajpur, Bardubhi and Jatudih, in the District Dhanbad.

And whereas Sarvashri Maharaj Singh, Amulya Singh and Jagdish Singh were found as persons interested under section 13 of the said Act in accordance with the authentication by the State Government authorities and accordingly compensation for an area of 0.68 acres of the said acquisition was assessed in their favour;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute as to the sufficiency of amount of the compensation offered and the amount so offered has been accepted by the persons interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Shri Rabneshwar Prasad Sinha, Additional Judicial Commissioner, Ranchi, for the purpose of determining the amount of compensation payable to the persons interested.

[No. F.C-5(9)/70.]

का० आ० 409—यतः कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन भारत सरकार के भूतत्त्व इस्पात और खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 2565 तारीख 21 अगस्त, 1965 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित का अर्जन किया है :—

- (1) मनीदी, गरबूडीह, बारदुभी, बालुडीह, डुबराजपुर और जातुडीह ग्रामों में 235.00 एकड़ माप की भूमि ; और
- (2) धनबाद जिले में गरबूडीह, बालुडीह, डुबराजपुर, बारदुभी और जातुडीह ग्रामों में 40.00 एकड़ माप की भूमि में, खनिजों के खनन, श्रिया, बोर करने खोदने, खदान के लिए और उनकी तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, कार्य करने और ले जाने के अधिकार।

और यतः राज्य सरकार प्राधिकारियों के अधिकरण के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन सर्व श्री, महाराजा सिंह, अमूल्य सिंह और जगदीश सिंह हितबद्ध व्यक्ति पाए गए थे और तदनुसार 0.68 एकड़ क्षेत्र के उक्त अर्जन के लिए प्रतिकर उनके पक्ष में निर्धारित किया गया था।

और यतः प्रस्थापित प्रतिकर की राशि की पर्याप्तता के बारे में विवाद होने से उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की राशि करार द्वारा नियत नहीं की जा सकी ; और इस प्रकार प्रस्थापित राशि हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा सविरोध ही स्वीकार की गई है।

अतः, अब कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की राशि को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा एक अधिकरण को गठित करती है जिसमें श्री रबनेश्वर प्रसाद सिन्हा, अपर न्यायिक आयुक्त, रांची होंगे।

[सं० फा० को० 3-5 (9) / 70]

S.O. 410.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines No. S.O. 2565, dated the 21st August, 1965, made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired:

- (i) Lands measuring 235.00 acres in villages Manidi, Garbhudih, Bardubhi, Baludih, Dubrajpur and Jatudih; and
- (ii) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in lands measuring 40.00 acres in villages Garbhudih, Baludih, Dubrajpur, Bardubhi and Jatudih, in the District Dhanbad.

And whereas Sarvashri Shashi Lal Singh, Indra Narain Singh and Jyoti Lal Singh were found as persons interested under section 13 of the said Act, in accordance with authentication by the State Government authorities and accordingly compensation for an area of 0.11 acres of the said acquisition was assessed in their favour;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute as to the sufficiency of amount of the compensation offered and the amount so offered has been accepted by the persons interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Shri Rabneshwar Prasad Sinha, Additional Judicial Commissioner, Ranchi, for the purpose of determining the amount of compensation payable to the persons interested.

[No. F.C3-5(9)/70.]

का० आ० 410.—अतः कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2565 तारीख 21 अगस्त, 1965 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित का अर्जन किया है :—

- (1) मनोदी, गरबूडीह, बारदुभी, बालुडीह, डुबराजपुर और जातुडीह ग्रामों में 235.00 एकड़ माप की भूमि ; और
- (2) धनबाद जिले में गरबूडीह, बालुडीह डुबराजपुर, बारदुभी और जातुडीह ग्रामों में 40.00 एकड़ माप की भूमि में, खनिजों के खनन, खदान क्रिया, बोर करने, खोदने के लिए और उन की तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, कार्य करने और ले जाने के अधिकार

और यतः राज्य सरकार प्राधिकारियों के अधिप्राणीकरण के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 13 की अधीन सर्वश्री शशि लाल सिंह, इन्द्र नारायण सिंह और ज्योती लाल सिंह हितबद्ध व्यक्ति पाए गए थे। और तदनुसार 0.11 एकड़ क्षेत्र के उक्त अर्जन के लिए प्रतिकर उनके पक्ष में निर्धारित किया गया था ;

और यतः प्रस्थापित प्रतिकर की राशि की पर्याप्तता के बारे में विवाद होने से उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की राशि करार द्वारा नियत नहीं की जा सकी ; और इस प्रकार प्रस्थापित राशि हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा सविरोध ही स्वीकार की गई है ;

अतः, अब कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार हितवद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर को राशि को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा एक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री रबनेश्वर प्रसाद सिन्हा, अपर न्यायिक आयुक्त, राँची होंगे।

[सं० फा० को० 3-5 (9)/70]

S.O. 411.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines No. S.O. 2565, dated the 21st August, 1965, made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired:

- (i) Lands measuring 235.00 acres in villages Manidh, Garbhudih, Bardubhi, Baludih, Dubrajpur and Jatudih; and
- (ii) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in lands measuring 40.00 acres in villages Garbhudih, Baludih, Dubrajpur, Bardubhi and Jatudih, in the District Dhanbad.

And whereas Sarvashri Indra Narain Singh and Shashi Lal Singh s/o Ajodya Singh were found as persons interested under section 13 of the said Act in accordance with authentication by the State Government authorities and accordingly compensation for an area of 0.80 acres of the said acquisition was assessed in their favour;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute as to the sufficiency of amount of the compensation offered and the amount so offered has been accepted by the persons interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Shri Rabneshwar Prasad Sinha, Additional Judicial Commissioner, Ranchi, for the purpose of determining the amount of compensation payable to the persons interested.

[No. F.C3-5(9)/70]

का० आ० 411.—यतः कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2565 तारीख 21 अगस्त, 1965 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित का अर्जन किया है :—

- (i) मनीरी, गरबूडीह, बारबुधी, बालुडीह, डुबराजपुर और जातुडीह ग्रामों में 235.00 एकड़ माप की भूमि, और
- (ii) धनबाद जिले में गरबूडीह, बालुडीह, डुबराजपुर, बारबुधी और जातुडीह ग्रामों में 40.00 एकड़ माप की भूमि में, खनिजों के खनन, खदान किया, बोर करने, खोदने के लिए और उन की तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, कार्य करने और ले जाने के अधिकार।

और यतः राज्य सरकार प्राधिकारियों के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन सर्वश्री इन्द्र नारायण सिंह और शशि लाल सिंह सुपुत्र अजोद्या सिंह हितवद्ध व्यक्ति पाए गए थे और तदनुसार 0.80 एकड़ क्षेत्र के उक्त अर्जन के लिए प्रतिकर उनके पक्ष में निर्धारित किया गया था ;

और यतः प्रस्थापित प्रतिकर की राशि की पर्याप्तता के बारे में विवाद होने से उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की राशि करार द्वारा नियत नहीं की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित राशि हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा सविरोध ही स्वीकार की गई है ,

अतः अब कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की राशि को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा एक अधिकरण को गठित करती है जिसमें श्री रबेश्वर प्रसाद सिन्हा अपर न्यायिक आयुक्त रांची होंगे।

[सं० का० को० 3-5(9)/70]

S.O. 412.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines No. S.O. 2565, dated the 21st August, 1965, made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired:

- (i) Lands measuring 235.00 acres in villages Manidi, Garbhudih, Bardubhi Baludih, Dubrajpur and Jatudih; and
- (ii) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in lands measuring 40.00 acres in villages Garbhudih, Baludih, Dubrajpur, Bardubhi and Jatudih, in the District Dhanbad.

And whereas Sarvashri Jyoti Lal Singh, Hemlal Singh, Biru Singh, Bistu Singh and Srilal Singh were found as persons interested under section 13 of the said Act in accordance with authentication by the State Government authorities and accordingly compensation for an area of 0.92 acres of the said acquisition was assessed in their favour;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute as to the sufficiency of amount of the compensation offered and the amount so offered has been accepted by the persons interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Shri Rabneshwar Prasad Sinha, Additional Judicial Commissioner, Ranchi, for the purpose of determining the amount of compensation payable to the persons interested.

[No. F.C3-5(9)/70.]

का० आ० 412.—यतः कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की उपधारा 9 के अधीन भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2565 तारीख 21 अगस्त, 1965 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित का अर्जन किया है :—

- (i) मनीदी, गरबूडीह, बारदुभी, बालुडीह, डुबराजपुर और जातुडीहा ग्रामों में 235.00 एकड़ माप की भूमि ; और
- (ii) धनबाद जिले में, गरबूडीह, बालुडीह, डुबराजपुर, बारदुभी, और जातुडीहा ग्रामों में 40.00 एकड़ माप की भूमि में, खनिजों के खनन, खदान क्रिया, बोर करने खादने के लिए और उन को नालाश करने की उन्हें प्राप्त करने, कार्य करने और ले जाने के अधिकार।

और यतः राज्य सरकार प्राधिकारियों के अधिप्रमाणीकरण के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन सर्वश्री ज्योति लाल सिंह, हेमलाल सिंह बोरु सिंह बिस्तु सिंह और श्रीलाल सिंह हितबद्ध व्यक्ति पाए गए थे और तदनुसार 0.92 एकड़ भूमि क्षेत्र के उक्त अर्जन के लिए प्रतिकर उनके पक्ष में निर्धारित किया गया था ;

और यतः प्रस्थापित प्रतिकर की राशि की पर्याप्तता के बारे में विवाद होने से उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की राशि करार द्वारा नियत नहीं की जा सकती और इस प्रकार प्रस्थापित राशि हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा अवरोध ही स्वीकार की गई है ;

अतः अश कोयलावाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदर्शित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की राशि को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा एक अधिकरण को गठित करती है जिममें श्री रवेनश्वर प्रसाद सिन्हा, अपर न्यायिक आयुक्त, रांची होंगे।

[सं. फा० को० 3-5(9)/70]

S.O. 413.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines No. S.O. 2565, dated the 21st August, 1965, made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired;

- (i) Lands measuring 235.00 acres in villages Manidi, Garbhudih, Bardubhi, Baludih, Dubrajpur and Jatudih; and
- (ii) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in lands measuring 40.00 acres in villages Garbhudih, Baludih, Dubrajpur, Bardubhi and Jatudih, in the District Dhanbad.

And whereas Sri Kashinath Chaudhary was found as person interested under section 13 of the said Act in accordance with the authentication by the State Government authorities accordingly compensation for an area 1.02 acres was assessed in his favour;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute as to the sufficiency of amount of the compensation offered and the amount so offered has been accepted by the persons interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Shri Rabneshwar Prasad Sinha, Additional Judicial Commissioner, Ranchi, for the purpose of determining the amount of compensation payable to the persons interested.

[No. F.C3-5(9)/70.]

का० आ० 413.—यतः कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2565 तारीख 21 अगस्त, 1965 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित का अर्जन किया है :—

- (i) मनीदी, गरबूडीह, बारदुभी, बालुडीह, डुबराजपुर और जातुडीह ग्रामों में 235.00 एकड़ माप की भूमि; और
- (ii) धनबाद जिले में गरबूडीह, बालुडीह, डुबराजपुर, बारदुभी और जातुडीह ग्रामों में 40.00 एकड़ माप की भूमि में, खनिजों के खनन, खदान क्रिया, बोर करने खोदने के लिए और उनकी तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, कार्य करने और लेजाने के अधिकार।

और यतः राज्य सरकार प्राधिकारियों के अधिप्रमाणीकरण के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन श्री काशीनाथ चौधरी हितबद्ध व्यक्ति पाया गया था और तदनुसार 1.02 एकड़ क्षेत्र के उक्त अर्जन के लिए प्रतिकर उसके पक्ष में निर्धारित किया गया था।

और यतः प्रस्थापित प्रतिकर की राशि की पर्याप्तता के बारे में विवाद होने से उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की राशि करार द्वारा नियत नहीं की जा सकी; और इस प्रकार प्रस्थापित राशि हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा सविरोध ही स्वीकार की गई है;

अतः, अब कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 को उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की राशि को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा एक अधिकरण को गठित करती है जिसमें श्री रबनेश्वर प्रसाद सिन्हा, अपर न्यायिक आयुक्त, रांची होंगे।

[सं० फा० को० 3-5(9)/70]

S.O. 414.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines No. S.O. 2565, dated the 21st August, 1965, made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired:

- (i) Lands measuring 235.00 acres in villages Manidi, Garbhudih, Bardubhi, Baludih, Dubrajpur and Jatudih; and
- (ii) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in lands measuring 40.00 acres in villages Garbhudih, Baludih, Dubrajpur, Bardubhi and Jatudih, in the District Dhanbad.

And whereas Sarvashri Bihari Mahto, Panchoo Mahto and Budhu Mahto were found as persons interested under section 13 of the said Act in accordance with the authentication by the State Government authorities and accordingly compensation for an area of 0.30 acres of the said acquisition was assessed in their favour;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute as to the sufficiency of amount of the compensation offered and the amount so offered has been accepted by the persons interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Shri Rabneshwar Prasad Sinha, Additional Judicial Commissioner, Ranchi, for the purpose of determining the amount of compensation payable to the persons interested.

[No. F.C3-5(9)/70.]

का० प्रा० 414.—यतः कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 2565 तारीख 21 अगस्त, 1965 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित का अर्जन किया है :—

- (i) मनीदी, गरबूडीह, बारदुभी, बालुडीह, डुबराजपुर और जातुडीह ग्रामों में 235.00 एकड़ माप की भूमि; और
- (ii) धनबाद जिले में गरबूडीह, बालुडीह, डुबराजपुर, बारदुभी और जातुडीह ग्रामों में 40.00 एकड़ माप की भूमि में, खनिजों के खनन, खदान किया, बोर करने, खोदने के लिए और उनकी तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, कार्य करने और ले जाने के अधिकार।

और यतः राज्य सरकार प्राधिकारियों के अधिप्रमाणिकरण के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन सर्वश्री बिहारी महतो, पंचू महतो और बुधु महतो हितबद्ध व्यक्ति पाये गये थे और तदनुसार 0.30 एकड़ क्षेत्र के उक्त अर्जन के लिए प्रतिकर उनके पक्ष में निर्धारित किया गया था;

और यतः प्रस्थापित प्रतिकर की राशि की पर्याप्तता के बारे में विवाद होने से उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की राशि करार द्वारा नियत नहीं की जा सकी; और इस प्रकार प्रस्थापित राशि हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा सविरोध ही स्वीकार की गई है ;

अतः, भव कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार हितबद्ध व्यक्तियों को संवेद्य प्रतिकर की राशि को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा एक अधिकरण को गठित करती है जिसमें श्री रबनेश्वर प्रसाद सिन्हा, अपर न्यायिक आयुक्त, रांची होंगे।

[सं० फा० को० 3-5(9)/70]

S.O. 415.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines No. S.O. 2565, dated the 21st August, 1965, made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired:

- (i) Lands measuring 235.00 acres in villages Manidi, Garbhudih, Bardubhi, Baludih, Dubrajpur and Jatudih; and
- (ii) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in lands measuring 40.00 acres in villages Garbudih, Baludih, Dubrajpur, Bardubhai and Jatudih, in the District Dhanbad.

And whereas Sarvashri Lalu Mahto, Babulal Mahto, Harilal Mahto alias Hari Boli Mahto, Birbal Mahtom, Pahlul Mahto, Ram Mahto, Karmu Mahto, Shrimati Roshani Mahtain, Shrimati Hemia Mahtain and Mahabir Mahto were found as persons interested under section 13 of the said Act in accordance with authentication by the State Government authorities accordingly compensation for an area of 2.21 acres was assessed in their favour;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute as to the sufficiency of amount of the compensation offered and the amount so offered has been accepted by the persons interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Shri Rabneshwar Prasad Sinha, Additional Judicial Commissioner, Ranchi, for the purpose of determining the amount of compensation payable to the persons interested.

[No. F.C3-5(9)/70.]

का० आ० 415.—यतः कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन भारत सरकार के भूतत्पूर्व इस्पात और खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2565 तारीख 21 अगस्त, 1965 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित का अर्जन किया है :—

- (i) मनीदी, गरबूडीह, बारदुभी, बालुडीह, डुबराजपुर और जातुडीह ग्रामों में 235.00 एकड़ माप की भूमि; और
- (ii) घनबाव जिले में गरबूडीह, बालुडीह, डुबराजपुर, बारदुभी और जातुडीह ग्रामों में 40.00 एकड़ माप की भूमि में, खनिजों के खनन, खदान क्रिया, बोर करने, खोदने के लिए और उनकी तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, कार्य करने और ले जाने के अधिकार।

और यतः राज्य सरकार प्राधिकारियों के अधिप्रमाणीकरण के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन सर्वश्री लालु महतो, बाबुलाल महतो, हरिलाल महतो उर्फ हरिबोल महतो, बीरबल महतो, पल्लु महतो, राम महतो, कर्मू महतो, श्रीमती रोशनी महताईन, श्रीमती हेमिया महताईन और महाबीर महतो हितबद्ध व्यक्ति पाये गये थे और तदनुसार 2.21 एकड़ क्षेत्र के उक्त अर्जन के लिए प्रतिकर उनके पक्ष में निर्धारित किया गया था;

और यतः प्रस्थापित प्रतिकर की राशि की पर्याप्तता के बारे में विवाद होने से उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की राशि करार द्वारा नियत नहीं की जा सकी; और इस प्रकार प्रस्थापित राशि हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा सविरोध ही स्वीकार की गई है;

अतः, अब कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार हितवद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की राशि को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा एक अधिकरण को गठित करती है जिसमें श्री रबनेश्वर प्रसाद सिन्हा, अपर न्यायिक आयुक्त, रांची होंगे।

[सं० फा० को० 3-5(9)/70]

S.O. 416.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines No. S.O. 2565, dated the 21st August, 1965, made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired;

(i) Lands measuring 235.00 acres in villages Manidi, Garbhudih, Bardubhi, Baludih, Dubrajpur and Jatudih; and

(ii) the rights to mine, quarry, bore dig and search for, win, work and carry away minerals in lands measuring 40.00 acres in villages Garbhudih, Baludih, Dubrajpur, Bardubhi and Jatudih, in the District Dhanbad.

And whereas Sarvashri Debu Mahto, and Shibu Mahto, s/o. Charku Mahto were found as persons interested under section 13 of the said Act, in accordance with the authentication, and accordingly compensation for an area 1.15 acres of the said acquisition was assessed in their favour;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute as to the sufficiency of amount of the compensation offered and the amount so offered has been accepted by the persons interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government, hereby constitutes a Tribunal consisting of Shri Rabneshwar Prasad Sinha, Additional Judicial Commissioner, Ranchi, for the purpose of determining the amount of compensation payable to the persons interested.

[No. F.C3-5(9)/70.]

फा० आ० 416.—यतः कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या फा० आ० 2565 तारीख 21 अगस्त, 1965 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित का अर्जन किया है :—

(i) मनीदी, गरबूडीह, बारदुभी, बालुडीह, डुबराजपुर और जातुडीह ग्रामों में 235.00 एकड़ माप की भूमि ; और

(ii) धनबाद जिले में गरबूडीह, बालुडीह, डुबराजपुर, बारदुभी और जातुडीह ग्रामों में 40.00 एकड़ माप की भूमि में, खनिजों के खनन, खदान क्रिया, बोर करने, खोदने के लिए और उनकी तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, कार्य करने और ले जाने के अधिकार।

और यतः राज्य सरकार प्राधिकारियों के अधिप्रमाणीकरण के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन सर्वश्री देबु महतो, और शिबु महतो सुपुत्र चरकु महतो हितवद्ध व्यक्ति पाये गये थे और तदनुसार 1.15 एकड़ क्षेत्र के उक्त अर्जन के लिए प्रतिकर उनके पक्ष में निर्धारित किया गया था;

और यतः प्रस्थापित प्रतिकर की राशि की पर्याप्तता के बारे में विवाद होने से उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की राशि करार द्वारा नियत नहीं की जा सकी ; और इस प्रकार प्रस्थापित राशि हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा सविरोध ही स्वीकार की गई है ;

अतः अब कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की राशि को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा एक अधिकरण को गठित करती है जिसमें श्री रबनेश्वर प्रसाद सिन्हा, अपर न्यायिक आयुक्त, रांची होंगे ।

[मे० फा० को० 3-5(9)/70]

S.O. 417.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines No. S.O. 2565, dated the 21st August, 1965, made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired;

- (i) Lands measuring 235.00 acres in villages Manidi, Garbhudih, Bardubhi, Baludih, Dubrajpur and Jatudih; and
- (ii) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in lands measuring 40.00 acres in villages Garbhudih, Baludih, Dubrajpur, Bardubhi and Jatudih, in the District of Dhanbad.

And whereas Sarvashri Mukut Dhari Singh, Kanthi Prasad Singh, Maharaj Singh, Vakil Singh, Radha Nath Singh, and Shrimati Butan Devi, w/o. Dari Singh were found as persons interested under section 13 of the said Act, in accordance with the authentication of State Government authorities and accordingly compensation for an area 0.54 acres of the said acquisition was assessed in their favour;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute as to the sufficiency of amount of the compensation offered and the amount so offered has been accepted by the persons interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Shri Rabneshwar Prasad Sinha, Additional Judicial Commissioner Ranchi, for the purpose of determining the amount of compensation payable to the persons interested.

[No. F.C3-5(9)/70.]

का० आ० 417.—यतः कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2565 तारीख 21 अगस्त, 1965 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित का अर्जन किया है :—

- (i) मनीडी, गरबूडीह, बारदुभी, बालुडीह, डुबराजपुर और जातुडीह ग्रामों में 235.00 एकड़ माप की भूमि ; और
- (ii) धनबाद जिले में गरबूडीह, बालुडीह, डुबराजपुर, बारदुभी और जातुडीह ग्रामों में 40.00 एकड़ माप की भूमि में, खनिजों के खनन, खदान किया, बोर करने, खोदने के लिए और उनकी तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, कार्य करने और ले जाने के अधिकार ।

और यतः राज्य सरकार प्राधिकारियों के अधिप्रमाणीकरण के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन सर्वश्री मुकुट धारी सिंह, कान्ति प्रसाद सिंह, महाराज सिंह, वकील सिंह, राधानाथ सिंह और श्रीमती बृटन देवी पत्नी धारी सैन हितबद्ध व्यक्ति पाये गये थे और तदनुसार 0.54 एकड़ क्षेत्र के उक्त अर्जन के लिए प्रतिकर उनके पक्ष में निर्धारित किया गया था ;

और यतः प्रस्थापित प्रतिकर की राशि की पर्याप्तता के बारे में विवाद होने से उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की राशि करार द्वारा नियत नहीं की जा सकी ; और इस प्रकार प्रतिस्थापित राशि हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा सविरोध ही स्वीकार की गई है ,

अतः अब कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की राशि को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा एक अधिकरण को गठित करती है जिसमें श्री रत्नेश्वर प्रसाद सिन्हा, अपर न्यायिक आयुक्त, रांची होंगे ।

[सं० फा० को० 3-5(9)/70]

के० सुब्रह्मण्यम, अपर सचिव ।

S.O. 418.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines and Fuel No. S.O. 2761, dated the 20th September, 1963, made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired;

- (i) Lands measuring 193.25 acres in villages Samsikhra, Dhandaber, Dhobni, Gopinathdih, Parasias and Garbhudih; and
- (ii) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in lands measuring 1405.25 acres in villages Parasias, Garbhudih, Manidi, Samsikhra, Panderkanali, Chirudi, Dhandabar, Dhobni, Gopinathdih, Chakphutaha, Rajesbera, Sabaldih and Phutaba, in the District Dhanbad.

And whereas Shrimati Kulda Mochin, w/o. Charan Mochi of village Putki the person interested has under section 13 of the said Act, preferred her claim to the competent authority for payment of compensation of 0.24 acres for the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by the persons interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Shri Rabneshwar Prasad Sinha, Additional Judicial Commissioner, Ranchi, for the purpose of determining the amount of compensation payable to the persons interested.

[No. F.C-5(9)/70.]

K. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 16th January 1971

S.O. 419.—IDRA/6/1/71.—In exercise of the powers conferred by Section of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (85 of 1951) read with, rules 5(i) and 8 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1962, the Central Government hereby appoints, till the 30th April, 1971, the Additional Secretary to the Government of Tamil Nadu, Industries Department, Madras, in place of

the Additional Secretary (Sugar) to the Government of Tamil Nadu, Industries Department, Madras (Ex-officio) to be a member of the Development Council established by the Order of the Government of India, in the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 1751/IDRA/6/3/69, dated the 1st May, 1969, for the Scheduled Industries engaged in the manufacture or production of sugar, and directs that the following amendment shall be made in the said Order, namely:—

In the said Order, for entry No. 16 relating to the Additional Secretary (Sugar) to the Government of Tamil Nadu, Industries Department, Madras (Ex-officio), the following entry shall be substituted, namely:—

“16. The Additional Secretary to the Government of Tamil Nadu, Industries Department, Madras.”

[No. 13(8)/68-LC.]

R. C. SETHI, Under Secy.

